facebook.com/thebharatshri
twitter.com/thebharatshri
website thebharatshri

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

भारत श्री

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

सोमवार, 02 फरवरी 2026 ● वर्ष 7 ● अंक 29 ● मूल्यः 5 रुपए

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का...

केंद्रीय बजट 2026–27

इलाज सस्ता, उत्पादन को बढ़ावा, निवेश पर सख्ती

राहत और सख्ती का मिला-जुला बजट, विकसित भारत 2047 की दिशा में सरकार का नया दांव

@ भारतश्री ब्यूरो

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026–27 का केंद्रीय बजट पेश किया। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, अमेरिका की ओर से लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ और सुस्त अंतरराष्ट्रीय मांग के बीच पेश यह बजट संतुलन साधने की कोशिश करता नजर आया। सरकार ने एक ओर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, ग्रीन एनर्जी और स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत दी है, तो दूसरी ओर शेयर बाजार से जुड़े सट्टा कारोबार और कुछ गतिविधियों को महंगा कर दिया है।सरकार का दावा है कि यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मजबूती देने वाला है। खास बात यह रही कि आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स में कोई नई राहत नहीं दी गई, लेकिन इलाज, ऊर्जा, निर्यात और विदेश से जुड़े खर्चों में कुछ अहम राहत जरूर दी गई है।

कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के मरीजों को बड़ी राहत

इस बजट की सबसे अहम घोषणा स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी रही। सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 जीवनरक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। इससे ये दवाएं भारतीय बाजार में सस्ती होंगी और मरीजों व उनके परिवारों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा।इसके साथ ही 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं और विशेष पोषण आहार (स्पेशल फूड) पर भी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। लंबे समय से इन बीमारियों से जूझ रहे मरीज और सामाजिक संगठन इस राहत की मांग कर रहे थे।विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल इलाज सस्ता होगा, बल्कि दुर्लभ बीमारियों के प्रति नीति-निर्माताओं की संवेदनशीलता भी सामने आती है।

मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा

बजट 2026–27 में सरकार ने 'मेक इन इंडिया' और निर्यात को रफ्तार देने पर खास ध्यान दिया है।सी-फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री इनपुट की सीमा 1 फीसदी से बढ़ाकर 3 फीसदी कर दी गई है। इससे मछली और समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।लेदर, सिंथेटिक फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए भी ड्यूटी-फ्री इनपुट और समयसीमा को बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे इन क्षेत्रों में उत्पादन लागत घटेगी और वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पाद ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे।माइक्रोवेव ओवन के कुछ जरूरी पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का भी ऐलान किया गया है, जिससे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को फायदा मिल सकता है।

क्या-क्या महंगा होगा

बजट के बाद कुछ चीजें और गतिविधियां महंगी हो सकती हैं। कुछ केमिकल्स जैसे पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड पर पहले मिलने वाली कस्टम ड्यूटी छूट खत्म कर दी गई है। अब इन पर 7.5 फीसदी तक ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा स्क्रैप, खनिज, शराब और तेंदूपत्ता की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह बढ़ने से इन क्षेत्रों में लागत बढ़ सकती है। इसका असर इनसे जुड़े उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है।केंद्रीय बजट २०२६–२७ से यह साफ होता है कि सरकार ने इस बार इलाज, उत्पादन, निर्यात और ग्रीन एनर्जी को सस्ता करने का रास्ता चुना है, जबकि वित्तीय लेन-देन और सट्टा गतिविधियों को महंगा किया है।कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स हटाना बजट का मानवीय चेहरा दिखाता है, वहीं शेयर बाजार में सख्ती से सरकार का संकेत है कि वह सट्टेबाजी की बजाय वास्तविक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहती है।हालांकि, मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत न मिलने से कुछ निराशा जरूर हाथ लगी है। अब यह देखना होगा कि बजट में दी गई रियायतों का फायदा जमीन पर कितनी तेजी से और कितनी हद तक लोगों तक पहुंच पाता है।

न्यूक्लियर पावर को दीर्घकालिक समर्थन

ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात होने वाले उपकरणों पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। यह कदम लंबी अवधि में परमाणु ऊर्जा को सस्ता और व्यवहारिक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।ग्रीन एनर्जी को लेकर बजट में कई राहतें दी गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), सोलर पैनल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई इनपुट्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।लिथियम-आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी कच्चे माल अब ड्यूटी फ्री होंगे। इसके अलावा सोलर पैनल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास के कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है।इससे EV, सोलर और बैटरी सेक्टर में उत्पादन लागत घटने की संभावना है। हालांकि, इसका फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा या नहीं, यह काफी हद तक कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीतियों पर निर्भर करेगा।

विदेश से जुड़े खर्चों में राहत

बजट में विदेश से जुड़े व्यक्तिगत खर्चों पर भी कुछ राहत दी गई है।निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए जाने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है। इससे विदेश से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम पहले से सस्ते हो सकते हैं।विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS) को 5 या 20 फीसदी से घटाकर फ्लैट 2 फीसदी कर दिया गया है, वह भी बिना किसी सीमा के।इसी तरह विदेश में पढ़ाई या इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसों पर 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर TCS अब 5 फीसदी की जगह 2 फीसदी लगेगा। इससे विदेश में पढ़ने या इलाज कराने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ राहत मिल सकती है।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग हुई महंगी

जहां एक ओर सरकार ने उत्पादन और उपभोग को सस्ता करने की कोशिश की है, वहीं वित्तीय लेन-देन को महंगा कर दिया गया है।फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया गया है। ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 फीसदी कर दिया गया है, जबकि ऑप्शन एक्सरसाइज पर टैक्स 0.125 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 फीसदी किया गया है।इससे फ्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग करना पहले से महंगा हो जाएगा। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अत्यधिक सट्टेबाजी पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है।

शेयर बायबैक पर प्रमोटर्स को झटका

कंपनियों के शेयर बायबैक को लेकर भी सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब प्रमोटर्स को शेयर बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स के साथ अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा। इससे बायबैक के जरिए मुनाफा निकालना कम आकर्षक हो सकता है।सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम में समानता आएगी और टैक्स से बचने के रास्ते सीमित होंगे।

MN DIVINE

ORDER ALL TYPES OF :

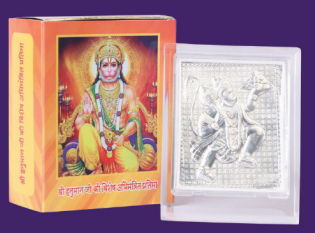

- POOJA SAMAGRI,
- AYURVEDIC MEDICINE
- AND PRATIMA.

NOW GET AT YOUR HOME ON

MNDIVINE.COM

ORDER NOW

https://mndivine.com/

HELPLINE : 9667793986
(10AM TO 6PM, MON-SAT)

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

नीतीश सरकार का पहला बजट

नौकरी, महिलाएं और खेती पर दांव, 3.70 लाख करोड़ से बदलेगा बिहार का रोडमैप

@ अभिषेक चौबे

3 फरवरी को बिहार सरकार वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है। नई नीतीश सरकार का यह पहला बजट होगा, इसलिए इस पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तरों पर खास नजर है। माना जा रहा है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि आने वाले पांच सालों की दिशा तय करने वाला रोडमैप बनेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और युवाओं के लिए नौकरी-रोजगार के नए रास्ते खोलने पर इस बजट का फोकस रहेगा।सरकार के सामने चुनौती भी कम नहीं है। चुनावी वादों और सामाजिक योजनाओं के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति दबाव में है। इसके बावजूद सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विकास की रफ्तार थमेगी नहीं। इसी संतुलन को साधने की कोशिश इस बजट में दिखाई दे सकती है।

करीब 3.70 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है बजट

वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, इस बार बिहार का बजट करीब 3 लाख 70 हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब 50 हजार करोड़ रुपए ज्यादा होगा। हालांकि, यह बढ़ोतरी पिछले साल के 57 हजार करोड़ रुपए के इजाफे से थोड़ी कम है। विशेषज्ञ इसे चुनावी साल खत्म होने और आर्थिक दबाव का असर मान रहे हैं। पिछले साल बजट में लगभग 13 फीसदी की वृद्धि हुई थी। सरकार इस बार भी उसी रफ्तार को बनाए रखने की कोशिश में है, ताकि विकास योजनाएं प्रभावित न हों। लेकिन यह साफ है कि हर विभाग को सीमित संसाधनों में ज्यादा असरदार नतीजे देने होंगे।

नौकरी और रोजगार: बजट का सबसे बड़ा एजेंडा

नीतीश सरकार ने अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को नौकरी या रोजगार देने का वादा किया है। 2026-27 का बजट इस वादे की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि पहले साल में ही करीब 20 लाख युवाओं को नौकरी या स्वरोजगार के अवसर दिए जाएं।इसके लिए हर जिले में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। बजट में इसके लिए करीब 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि जब तक बिहार में उद्योग नहीं लगेंगे, तब तक पलायन की समस्या खत्म नहीं होगी।आज स्थिति यह है कि बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना आय देश में सबसे कम—करीब 69 हजार रुपए है। बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाते हैं। सरकार चाहती है कि रोजगार राज्य के भीतर पैदा हो, ताकि लोगों को अपने घर-परिवार से दूर न जाना पड़े।अगर उद्योग और रोजगार पर सही तरीके से निवेश हुआ तो बेरोजगारी कम होगी, पलायन रुकेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। स्थानीय बाजार मजबूत होंगे और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी।

बिहार को नई पहचान देने की कोशिश

इस बजट में उद्योग और निवेश पर खास जोर रहने की उम्मीद है। निजी निवेश को आकर्षित करने, टेक हब विकसित करने और औद्योगिक विस्तार के लिए बड़ी राशि रखी जा सकती है। अनुमान है कि उद्योगों के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2500 करोड़ रुपए और कृषि से जुड़े उद्योगों के लिए करीब 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।हाल ही में राज्य सरकार ने 'बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2026' को मंजूरी दी है। इसके तहत आईटी, बैंकिंग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बिहार में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित करने वाली कंपनियों को 50 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।

खेती और किसानों पर फोकस

अगर बड़ी कंपनियां बिहार में आती हैं तो स्थानीय युवाओं को अच्छी नौकरियां मिलेंगी। आईटी और सर्विस सेक्टर के विकास से राज्य की छवि बदलेगी और निवेश का माहौल बनेगा।बिहार की बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। ऐसे में किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। बजट में मखाना, डेयरी और 'हर खेत को पानी' जैसी योजनाओं के लिए खास इंतजाम हो सकते हैं।सरकार का लक्ष्य है कि कृषि को सिर्फ गुजारे का साधन नहीं, बल्कि मुनाफे का क्षेत्र बनाया जाए। इसके लिए सिंचाई, भंडारण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर निवेश बढ़ाया जाएगा।किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहरों पर दबाव कम होगा।

शिक्षा पर बड़ा दांव

2026-27 के बजट में शिक्षा विभाग को करीब 70 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 10 हजार करोड़ रुपए ज्यादा होगा। खास बात यह है कि उच्च शिक्षा का बजट लगभग दोगुना हो सकता है।पिछले वित्त वर्ष में शिक्षा विभाग का बजट करीब 60,964 करोड़ रुपए था, जबकि खर्च इससे ज्यादा हुआ। इस बार सरकार पहले से बेहतर योजना के साथ आगे बढ़ना चाहती है।राज्य में करीब 6 लाख शिक्षक कार्यरत हैं और टीआरई-4 के तहत 27 हजार नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। बजट में वेतन भुगतान और स्कूल-कॉलेजों के बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया जाएगा। स्कूलों में नए भवन बनेंगे, डेस्क-बेंच और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी। शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और लंबे समय में इसका असर रोजगार और सामाजिक विकास पर पड़ेगा।

महिलाओं को 2-2 लाख रुपए

सात निश्चय-3 के तहत सरकार ने 94 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपए तक की सहायता देने का ऐलान किया है। बजट में इसके लिए पर्याप्त फंड का इंतजाम किया जाएगा।पहले चरण में 1.56 करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपए दिए गए थे। जिन महिलाओं ने इस राशि का उपयोग रोजगार शुरू करने में किया है, उन्हें अगली किस्त के रूप में 2 लाख रुपए मिलेंगे।ग्रामीण विकास विभाग को इसके लिए करीब 17 हजार करोड़ रुपए मिलने की संभावना है।महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी। हर परिवार में एक महिला उद्यमी का सपना सरकार साकार करना चाहती है, जिससे सामाजिक बदलाव भी आएगा।

सड़कें और बुनियादी सुविधाएं

सरकार का दावा है कि यह बजट आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाला होगा। सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी खर्च बढ़ाया जाएगा।शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर रहेगा, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचे।नीतीश सरकार का यह पहला बजट संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ आर्थिक दबाव हैं, दूसरी तरफ बड़े वादे। नौकरी, महिलाएं, किसान और शिक्षा,इन चार स्तंभों पर टिका यह बजट अगर सही तरीके से लागू हुआ, तो बिहार की तस्वीर बदल सकता है।

संघ बजट 2026: क्या यह विकास को गति देगा और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा?

बजट की मुख्य बातें: एक नजर में समझें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में संघ बजट 2026-27 पेश किया। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर देता है। अर्थव्यवस्था की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी विकास दर 7.4 प्रतिशत रह सकती है, जबकि अगले साल 6.8 से 7.2 प्रतिशत तक। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 12.2 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया है, जो पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ से ज्यादा है। इसका मतलब है कि सड़कें, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे पर ज्यादा पैसा लगेगा। बजट में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड शुरू किया गया है, जो निजी कंपनियों को जोखिम से बचाएगा। विदेशी निवेशकों के लिए निवेश सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत किया गया है। छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर चार राज्यों- ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनेंगे, और हर राज्य में तीन केमिकल पार्क भी। रेलवे में सात नए पर्यावरण अनुकूल पैसेंजर कॉरिडोर जैसे मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद और हैदराबाद-बेंगलुरु बनाए जाएंगे। सरकार का कर्ज लेने का लक्ष्य 17.2 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन नेट उधार 11.7 लाख करोड़ रहेगा। महंगाई कम है, सिर्फ 1.7 प्रतिशत औसत, और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 709 अरब डॉलर से ज्यादा। बजट में नौकरियां बढ़ाने पर फोकस है, जैसे सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और क्लाउड सर्विस कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स छूट। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे निजी कंपनियां अभी निवेश कम कर रही हैं। कुल मिलाकर, यह बजट विकास को तेज करने और समावेशी विकास पर केंद्रित है, जो आम लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी खर्च से निजी क्षेत्र भी आगे आएगा, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं असर डाल सकती हैं। यह बजट भारत को विकसित बनाने की दिशा में एक कदम है।

विकास को बढ़ावा: बजट की योजनाएं कैसे मदद करेंगी?

बजट 2026 में विकास को गति देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार का मानना है कि मजबूत घरेलू मांग, निजी खपत और निवेश से अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। जीडीपी विकास को बनाए रखने के लिए कैपेक्स पर जोर है, जो नौकरियां पैदा करेगा और आय बढ़ाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ का खर्च शहरों और गांवों को जोड़ेगा, जैसे टियर-2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी सुविधाएं। आर्थिक सर्वे कहता है कि नियामक सुधार और मजबूत आधार से विकास को सहारा मिलेगा। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए पीपीपी मॉडल में तीन साल की पाइपलाइन बनेगी, और 10 लाख करोड़ रुपये के सरकारी एसेट्स को रिसाइकल किया जाएगा। बायोफार्मा स्ट्रैटेजी और आयुर्वेद के तीन नए संस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करेंगे। निर्यात को बढ़ाने के लिए टैरिफ सुधार और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट है। लेकिन वैश्विक चुनौतियां जैसे व्यापार बाधाएं और सप्लाई चेन समस्याएं असर डाल सकती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकारी कैपेक्स से निजी निवेश आएगा, जो पिछले 13 साल से 12 प्रतिशत जीडीपी पर अटका है। महंगाई कम होने से आम आदमी को राहत है, और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए PROI की सीमा बढ़ाई गई। छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए फंड से रोजगार बढ़ेगा। कुल मिलाकर, बजट संतुलित विकास पर फोकस करता है, जहां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को फायदा हो। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अगर निजी कंपनियां साथ दें, तो विकास 7 प्रतिशत से ऊपर रह सकता है, वरना चुनौतियां बनी रहेंगी। यह बजट भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाने की कोशिश है, जो लंबे समय में फल दे सकती है।

निजी निवेश को प्रोत्साहन: क्या बजट सफल होगा?

निजी निवेश को बढ़ाने के लिए बजट में कई उपाय हैं, लेकिन चुनौतियां भी सामने हैं। सरकार का कैपेक्स बढ़ाना निजी क्षेत्र को आकर्षित करने का तरीका है, ताकि वे इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा लें। इंफ्रा रिस्क गारंटी फंड से निर्माण के दौरान जोखिम कम होगा, जो निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा। विदेशी कंपनियों के लिए क्लाउड सर्विस पर टैक्स छूट 2047 तक है, अगर वे भारत के डेटा सेंटर इस्तेमाल करें। SME के लिए 10,000 करोड़ का फंड 'फ्यूचर चैंपियंस' बनाएगा। लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि निजी निवेश 2012 से फ्लैट है, क्योंकि मांग कम है और क्षमता अतिरिक्त। सरकारी उधार बढ़ने से ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं, जो निजी निवेश को प्रभावित करेगा। विदेशी पूंजी का बहाव कम होना चिंता है, जिससे रुपया कमजोर हुआ। बजट में PROI की निवेश सीमा बढ़ाकर इस कमी को पूरा करने की कोशिश है। पीडब्ल्यूसी जैसे संगठन कहते हैं कि पीपीपी और एसेट रिसाइकल से निजी निवेश बढ़ेगा, जैसे फ्रेट कॉरिडोर में 20-25,000 करोड़ का निजी पैसा। सेमीकंडक्टर मिशन से हाई-टेक निवेश आएगा। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अगर वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ीं, तो निजी कंपनियां सतर्क रहेंगी। सरकार का फोकस समावेशी विकास पर है, जहां MSME और स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिले। कुल मिलाकर, बजट निजी निवेश को बूस्ट देने की दिशा में है, लेकिन सफलता इस पर निर्भर करेगी कि कंपनियां कितना विश्वास दिखाती हैं। यह एक विचारणीय बिंदु है कि सरकारी प्रयासों के बावजूद, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए और सुधार जरूरी हो सकते हैं।

बुनियादी ढांचे पर जोर: विकास की नींव मजबूत होगी?

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को राजा माना गया है, जो विकास की नींव रखेगा। कैपेक्स को 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाने से सड़कें, रेलवे और वाटरवेज मजबूत होंगे। सात नए रेल कॉरिडोर पर्यावरण अनुकूल होंगे, जो यात्रा को आसान बनाएंगे। 20 नए नेशनल वाटरवेज पांच साल में शुरू होंगे। केमिकल पार्क और रेयर अर्थ कॉरिडोर से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, जो आयात कम करेगा। इंफ्रा रिस्क फंड से निजी कंपनियां जोखिम लेने को तैयार होंगी। सरकार तीन साल की पीपीपी पाइपलाइन बनाएगी, और CPSE के एसेट्स से REITs शुरू होंगे। शहरों में पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले इलाकों पर फोकस है, जो टियर-2 शहरों को बढ़ावा देगा। लेकिन सरकारी उधार बढ़ने से ब्याज दरें प्रभावित हो सकती हैं, जो निजी निवेश को रोक सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि कैपेक्स से रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में गति आएगी। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? वैश्विक चुनौतियां जैसे संसाधन की कमी और नई तकनीकें दबाव डाल सकती हैं। बजट में जल, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान है। कुल मिलाकर, इंफ्रा पर जोर से लंबे समय में विकास मजबूत होगा, लेकिन निजी भागीदारी जरूरी है। यह बजट सोचने पर मजबूर करता है कि सरकारी खर्च कितना निजी निवेश को खींचेगा।

चुनौतियां और संभावनाएं: एक संतुलित नजरिया

बजट 2026 विकास और निवेश को बढ़ावा देने का वादा करता है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जीडीपी 7 प्रतिशत से ऊपर रखने के लिए सरकारी कैपेक्स जरूरी है, लेकिन निजी निवेश कम होना चिंता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि मांग कम होने से फैक्टरियां पूरी क्षमता पर नहीं चल रही हैं। विदेशी पूंजी का बाहर जाना और रुपए की कमजोरी असर डाल रही है। बजट में इनके लिए उपाय हैं, जैसे निवेश सीमा बढ़ाना और टैक्स छूट। लेकिन सरकारी उधार 17.2 लाख करोड़ होने से बाजार में पैसा कम हो सकता है, जो निजी कंपनियों के लिए मुश्किल बनेगा। फिस्कल डेफिसिट 4.4 प्रतिशत पर रखना अच्छा है, जो स्थिरता दिखाता है। नौकरियां बढ़ाने के लिए स्किलिंग और SME सपोर्ट है, जो युवाओं को फायदा देगा। वैश्विक स्तर पर व्यापार बाधाएं और सप्लाई चेन समस्याएं भारत को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन भारत की मजबूत घरेलू मांग और रिजर्व से सहारा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट संतुलित है, जहां विकास, नौकरियां और निवेश पर फोकस है। लेकिन सफलता इस पर निर्भर करेगी कि निजी क्षेत्र कितना सक्रिय होगा। यह विचारणीय है कि क्या बजट वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को तेज विकास की राह पर रख पाएगा। कुल मिलाकर, बजट उम्मीद जगाता है, लेकिन असली परीक्षा कार्यान्वयन में होगी।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत का रहस्य: कई इंजेक्शन, कंपाउंडर पर सवाल और छिपी सच्चाई

साध्वी प्रेम बाईसा: एक युवा कथावाचक की कहानी

साध्वी प्रेम बाईसा राजस्थान के जोधपुर के पास बोरणदा आश्रम में रहने वाली 25 साल की युवा कथावाचक थीं। वे सनातन धर्म की बातें करती थीं और भजन गाती थीं, जिससे वे पश्चिमी भारत में काफी मशहूर हो गई थीं। उनका जन्म बालोतरा जिले के परेऊ गांव में हुआ था और उनके पिता महंत वीरम नाथ भी आध्यात्मिक गुरु हैं। बचपन से ही प्रेम बाईसा को धार्मिक कहानियां सुनाने का शौक था। वे नाथ संप्रदाय से जुड़ी थीं और भगवा कपड़े पहनकर प्रवचन देती थीं। उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर थे, जहां वे अग्नि परीक्षा जैसी पुरानी कहानियों पर बात करती थीं। लेकिन 28 जनवरी 2026 को उनकी अचानक मौत ने सबको चौंका दिया। वे कुछ दिनों से बुखार और गले की तकलीफ से परेशान थीं। परिवार ने घर पर ही इलाज करवाया, लेकिन हालत बिगड़ गई। मौत के बाद उनके गांव में उन्हें बैठी मुद्रा में समाधि दी गई। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे क्या यह सामान्य मौत थी या कोई बड़ी साजिश। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक मौत का साफ कारण नहीं पता चला। प्रेम बाईसा की मौत से उनके चाहने वाले दुखी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वे ब्लैकमेल का शिकार थीं, लेकिन परिवार इसे गलत इंजेक्शन की वजह बताता है। यह मामला अब राजनीतिक भी बन गया है, जहां आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने सीबीआई जांच की मांग की है। कुल मिलाकर, प्रेम बाईसा की जिंदगी एक प्रेरणा थी, लेकिन उनकी मौत एक बड़ा रहस्य बन गई है। क्या जांच से सच्चाई सामने आएगी, यह देखना बाकी है।

मौत का दिन: कई इंजेक्शन और अचानक बिगड़ी तबीयत

28 जनवरी 2026 को साध्वी प्रेम बाईसा आश्रम में थीं और बुखार से पीड़ित थीं। उनके पिता वीरम नाथ ने बताया कि गले में दर्द था और एक कार्यक्रम जाना था, इसलिए तेजी से ठीक होने के लिए कंपाउंडर को बुलाया गया। कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित आया, जो परिवार को पहले से जानता था। उसने पहले डेक्सोना इंजेक्शन लगाया, जो सूजन और एलर्जी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हालत नहीं सुधरी, तो उसने कई और इंजेक्शन दिए। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंजेक्शन लगने के 30 सेकंड से 5 मिनट के अंदर ही प्रेम बाईसा की हालत बिगड़ गई। वे जोर से चीखीं, सांस लेने में तकलीफ हुई और मुंह से झाग आने लगा। आश्रम में मौजूद सुरेश ने देखा कि उनके नाखून हरे पड़ गए थे। परिवार उन्हें तुरंत प्रेक्षा अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर प्रवीण जैन ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि वे पहले से ही मरी हुई लग रही थीं। अस्पताल ने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल जाने की सलाह दी, लेकिन पिता ने शव को अपनी गाड़ी में ले लिया। कंपाउंडर ने इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह पर दिए थे, लेकिन क्या वे सही थे, यह जांच का विषय है। पुलिस ने कंपाउंडर के सामान को जब्त कर लिया। यह घटना सामान्य इलाज की लगती है, लेकिन कई इंजेक्शन देने से सवाल उठते हैं कि क्या कोई गलती हुई या जानबूझकर कुछ मिलाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि डेक्सोना सामान्य है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नुकसान कर सकता है। परिवार का मानना है कि गलत दवा दी गई, जबकि कुछ लोग इसे हादसा मानते हैं। जांच से पता चलेगा कि इंजेक्शन में क्या था और क्यों हालत इतनी तेजी से बिगड़ी।

परिवार का दर्द: आरोप, शंकाएं और न्याय की गुहार

साध्वी प्रेम बाईसा के पिता वीरम नाथ ने मौत को बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगने के बाद बेटी की नाखून काले पड़ गए, जो जहर की निशानी हो सकती है। वीरम नाथ का कहना है कि कंपाउंडर ने गलत इंजेक्शन दिया, जिससे 5 मिनट में मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल में डॉक्टर से बात की, लेकिन शव को आश्रम ले गए क्योंकि भीड़ थी। सुरेश नाम के गवाह ने बताया कि प्रेम बाईसा ने गिरते समय पिता से कहा, "मुझे न्याय दिला देना।" सुरेश ने सीपीआर भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परिवार का मानना है कि यह हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी चाल है। वे कहते हैं कि प्रेम बाईसा कुछ दिनों से तनाव में थीं, लेकिन वजह नहीं बताई। पिता ने आरोप लगाया कि कंपाउंडर देवी सिंह को अच्छे से जानते थे, लेकिन अब उसकी भूमिका संदिग्ध लगती है। परिवार ने पुलिस से गहन जांच की मांग की है और कहा कि मौत के पीछे कोई बड़ा राज हो सकता है। कुछ लोग परिवार पर ही सवाल उठाते हैं कि पोस्टमार्टम क्यों टाला, लेकिन वीरम नाथ कहते हैं कि वे दुख में थे। कुल मिलाकर, परिवार दुखी है और चाहता है कि सच्चाई सामने आए। वे मानते हैं कि प्रेम बाईसा मजबूत थीं और कभी हार नहीं मानती थीं। लेकिन अब न्याय की उम्मीद पुलिस पर है। यह पक्ष दिखाता है कि मौत सिर्फ चिकित्सा गलती नहीं, बल्कि शायद कोई छिपी साजिश हो सकती है। जांच से परिवार की शंकाएं दूर होंगी या नई बातें निकलेंगी, यह समय बताएगा।

पुलिस की तहकीकात: कंपाउंडर पर नजर और एसआईटी की भूमिका

पुलिस ने साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की जांच तेज कर दी है। कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ हो रही है। पुलिस पूछ रही है कि इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह पर दिए गए थे या नहीं, और उनमें क्या दवा थी। उसके सामान को जब्त किया गया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई गई है, जो मेडिकल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और आश्रम को सील करके जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का साफ कारण नहीं मिला, इसलिए विसरा को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने में समय लगेगा, लेकिन पुलिस जहर या गलत दवा के एंगल से देख रही है। आश्रम के सीसीटीवी फुटेज भी जांच में हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे गायब हैं। पुलिस ने परिवार और अस्पताल स्टाफ से बात की। अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने कहा कि प्रेम बाईसा पहले से मरी हुई लग रही थीं। पुलिस का कहना है कि यह मामला संदिग्ध है, लेकिन अभी हत्या या आत्महत्या कुछ साफ नहीं। वे पुरानी शिकायतों को भी देख रहे हैं। जांच अधिकारी शकील अहमद ने कहा कि सभी पहलू जांचे जा रहे हैं। कुछ लोग सीबीआई जांच मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि वे पूरी कोशिश कर रही हैं। यह जांच दिखाती है कि मौत के पीछे कई परतें हैं। क्या कंपाउंडर दोषी है या कोई और, यह रिपोर्ट से पता चलेगा। पुलिस बैलेंस तरीके से काम कर रही है, ताकि कोई पक्ष नजरअंदाज न हो।

बाकी रहस्य: सोशल मीडिया पोस्ट और पुरानी ब्लैकमेल की बात

साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद उनका इंस्टाग्राम पोस्ट चर्चा में है। मौत के 3-4 घंटे बाद पोस्ट आया, जिसमें अग्नि परीक्षा और न्याय की बात थी। पिता वीरम नाथ ने कहा कि यह उनके सोशल मीडिया हैंडलर ने अंतिम विदाई के रूप में डाला था। लेकिन कई लोग इसे सुसाइड नोट मानते हैं, जो मौत को और रहस्यमय बनाता है। पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है कि यह कब और कैसे डाला गया। इसके अलावा, 6 महीने पहले प्रेम बाईसा ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके स्टाफ ने एक डॉक्टर्ड वीडियो से ब्लैकमेल किया। वीडियो 2021 का था, लेकिन 2025 में फिर एफआईआर हुई। क्या यह ब्लैकमेल मौत से जुड़ा है, पुलिस देख रही है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि प्रेम बाईसा तनाव में थीं और सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही थीं। परिवार कहता है कि पोस्ट सिर्फ विदाई थी, लेकिन सवाल उठते हैं कि मौत के बाद क्यों डाला गया। पुरानी शिकायत में 20 लाख की फिरौती की बात थी। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो उन्हें परेशान कर रहे थे। यह पक्ष दिखाता है कि मौत सिर्फ इंजेक्शन की नहीं, बल्कि पुरानी दुश्मनी या मानसिक दबाव की भी हो सकती है। जांच से पता चलेगा कि क्या ब्लैकमेलर शामिल थे या यह अलग मामला है।

राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक

भारत श्री

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम

सोमवार, 02 फरवरी 2026 , विक्रम संवत 2080

UGC सरकार और सुप्रीम कोर्ट

पिछले तीन-चार दिनों से यूजीसी के मामले में जो घटनाक्रम चला वह मेरे लिए तो एक सपना सरीके था। हर क्षण परिस्थितियों बदल जाती थी और मैं सोच ही नहीं पाता था कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है कौन कर रहा है और परिणाम क्या होगा। क्योंकि मैं कुछ सोच पाता तब तक सारा वातावरण बदल जाता था। कल इस घटना का पटाक्षेप हुआ और तब यह बात कुछ कुछ दिखने लगी है कि यह सारी घटना दो खिलाड़ियों के बीच शह और मात के खेल में चल रही थी। एक तरफ थे दिग्विजय सिंह और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। एक तरफ दिग्विजय सिंह के साथ सारे कम्युनिस्ट थे और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के साथ कुछ बुद्धिजीवी सवर्ण थे। कभी दिखता था कि दिग्विजय सिंह की टीम भारी पड़ रही है और अब दिखने लगा कि दिग्विजय सिंह की टीम पूरी तरह चारों खाने चित हो गई है। मोदी की टीम ने उनको धोबिया पाट मार दिया है । मैं यह नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी ने यह सारा कार्य योजना अनुसार किया या स्वाभाविक तरीके से होता रहा या तत्काल कुछ नीतियों में सुधार करते रहे हुआ चाहे जो भी हो लेकिन मैदान में कम्युनिस्ट और दिग्विजय सिंह चारों खाने चित पड़े हैं। साथ ही जो अवर्ण बुद्धिजीवी अपने को मजबूत होता देख रहे थे उन्हें भी अब कुछ कुछ नुकसान समझ में आ रहा है । मेरे विचार से जिस सुप्रीम को माध्यम बनाकर इस भूत को जिंदा किया गया था उस सुप्रीम कोर्ट को माध्यम बनाकर सरकार ने इस घटना को श्मशान तक पहुंचा दिया। इस सारे टकराव से अब समाज को एक लाभ हुआ है कि आरक्षण पर एक नई बहस शुरू होगी अब तक आरक्षण का जो समाधान खोजा जहां था अब उससे कोई अलग समाधान खोजने की भी चर्चा शुरू होगी। हो सकता है कि आरक्षण का एक दीर्घकालिक समाधान जो हम लोग सोच रहे हैं उस समाधान पर भी चर्चा शुरू हो जाए। मैं अब भी मानता हूं कि आरक्षण का दीर्घकालिक समाधान श्रम और बुद्धि के बीच बढ़ती हुई खाई को पाटने के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है लेकिन देखिए इसका नंबर कब आता है । मैं इस सारे घटनाक्रम से तीन-चार दिनों तक बहुत दुखी था लेकिन अच्छा परिणाम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है।

ज्ञानेंद्र आर्य

बजट 2026 :चुनौतियों और यथार्थ का संतुलन

@ **अनुराग पाठक**

हर साल बजट आते ही देश की नब्ज़ कुछ तेज़ चलने लगती है—किसको राहत मिलेगी, किस पर बोझ बढ़ेगा और आने वाले साल की आर्थिक दिशा क्या होगी? इस बार का बजट भी कोई अपवाद नहीं था। उम्मीदों के आसमान थे, ज़रूरतों की लंबी सूची थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंद पड़ती रफ्तार सामने थी। ऐसे समय में सरकार ने एक ऐसा खाका पेश किया है जो न तो पूरी तरह लोकलुभावन है, न पूरी तरह कठोर आर्थिक गणना का दस्तावेज़—बल्कि दोनों के बीच कहीं खड़ा एक संतुलित बजट है।सबसे पहले बात राजस्व और घाटे की। लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं, महंगाई की उछाल और तेल कीमतों की ऊंची उड़ान के बीच भी सरकार ने राजकोषीय घाटा घटाकर 5.1 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य महत्वाकांक्षी भी है और ज़रूरी भी। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में निवेशक भारत की आर्थिक साख को इन्हीं संकेतकों से तौलते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह लक्ष्य बहुत अधिक तंग नज़रिये से बनाया गया है? क्योंकि अगर राजस्व अनुमान से कम आता है तो कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं पर दबाव पड़ेगा। संतुलन का यही सूत्र इस बजट की असली चुनौती है।

अर्थव्यवस्था की रीढ़—ग्रामीण भारत—को इस बार बजट की धड़कन कहा जा सकता है। कृषि क्षेत्र पर दबाव, किसानों की आय का संकट, ग्रामीण बेरोज़गारी और छोटे शहरों में बढ़ती महंगाई, इन सबने सरकार को मजबूर किया कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता मिले। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, ग्रामीण सड़क निर्माण और फसल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। यह कदम स्वागतयोग्य है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इन योजनाओं का असर ज़मीन पर दिखाई दे। कागज़ पर आवंटन बढ़ाने से कभी भी खेतों में हरियाली नहीं आती। क्रियान्वयन वही पुराना सच है, जो हर बजट के बाद भुला दिया जाता है।रोज़गार के मोर्चे पर सरकार ने बुनियादी ढांचा निर्माण को रोजगार-उत्पादन की मशीन के रूप में पेश किया है। हाईवे, रेलवे, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और ऊर्जा परियोजनाओं पर बढ़ा हुआ खर्च निकट भविष्य में नौकरियां पैदा कर सकता है। खासकर युवाओं के लिए, जो पिछले कुछ वर्षों से नौकरी की मंदी का सामना कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसे रोजगार अस्थायी और प्रोजेक्ट-बेस्ड होते हैं। भारत के सामने असली चुनौती कौशल आधारित, स्थायी और औपचारिक रोजगार का निर्माण है। यह लक्ष्य तभी संभव होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुनर्जीवित किया जाए और छोटे-मझोले उद्योगों को सस्ती पूंजी तथा तकनीकी समर्थन मिले। इसके लिए किए गए प्रावधान अच्छे संकेत जरूर देते हैं, पर अभी यह दिशा-निर्देश अधिक हैं, समाधान कम।मध्यम वर्ग की उम्मीद हमेशा की तरह कर प्रणाली में राहत की रहती है। इस वर्ग को सीधे तौर पर बड़ी रियायतें तो नहीं मिलीं, पर टैक्स ढांचे को सरल बनाने की घोषणा निश्चित रूप से भविष्य के लिए एक संकेत देती है। नीति-निर्माताओं को समझना होगा कि मध्यम वर्ग केवल टैक्स देने वाला वर्ग नहीं है; यह वही वर्ग है जो अर्थव्यवस्था की खपत, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास बाजार को मजबूत बनाए रखता है। इसके हाथ में थोड़ी अतिरिक्त राशि अर्थव्यवस्था में कई गुना प्रभाव डाल सकती है।

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं।स्वरोज़गार के लिए विशेष फंड, महिला किसान समूहों को सहयोग और महिला सुरक्षा से जुड़े प्रावधान। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं सबसे बड़ा अवसर छुपा है। खासकर तब, जब देश में ग्रामीण हस्तशिल्प और स्थानीय उद्यम बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र बनते जा रहे हैं। यदि इन योजनाओं को सही दिशा और निगरानी मिले, तो यह न सिर्फ महिलाओं की आय बढ़ा सकती हैं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा दे सकती हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्रों में आवंटन वृद्धि स्वागतयोग्य है, पर चिंता इस बात की है कि क्या यह बढ़ोतरी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है? कोविड ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश कोई विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। वहीं, शिक्षा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक प्रशिक्षण अभी भी कमजोर कड़ियाँ हैं। बजट एक दिशा प्रदान करता है, लेकिन तेजी उसी दिन आएगी जिस दिन निवेश और कार्यान्वयन दोनों धरातल पर साथ चलेंगे।सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह बजट आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव लाएगा? महंगाई अभी भी लोगों की जेब पर सबसे भारी बोझ है। दालें, सब्ज़ियां, दूध, गैस, आवास किराया,सब चीज़ों ने पिछले वर्षों में आम आदमी की सांसें और फूली हैं। जब तक आपूर्ति तंत्र मजबूत नहीं होता, कृषि उत्पादन लागत कम नहीं होती और बाजारों में पारदर्शिता नहीं बढ़ती, तब तक बजट में दिए गए वादे काग़ज़ पर ही चमकते रहेंगे।

कुल मिलाकर, यह बजट एक संतुलित कोशिश है..न बहुत साहसी, न बहुत सतर्क। सरकार ने अर्थव्यवस्था को स्थिर मार्ग पर रखने की कोशिश की है, लेकिन जनता यह भी चाहती है कि स्थिरता के साथ अवसरों का विस्तार भी दिखाई दे। बजट कोई जादुई छड़ी नहीं होता; यह एक ऐसा नक्शा है जिसमें दिशा तय की जाती है। असली यात्रा तो अगले बारह महीने में होगी, जब यह तय होगा कि यह बजट काग़ज़ों पर अधिक जीवित रहा या जमीन पर।

जुबानी तीर

“ यह बजट रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देता है और प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत की सोच का मजबूत आधार है। बिना तथ्यों के बयान देने से बचना चाहिए।

राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री)

“ यह बजट भारत के असली संकटों के प्रति अँधा है — युवाओं के लिए नौकरी नहीं, किसानों के लिए राहत नहीं। सरकार को वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

राहुल गांधी (नेता प्रतिपक्ष)

“ यह बजट गरीब किसान और गाँव वालों की समझ से बाहर है — यह उनकी ज़रूरतों के अनुरूप नहीं है। यह बजट नौकरी प्रदान नहीं कर सकता।

अखिलेश यादव (सपा प्रमुख)

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक डॉ. महिमा मक्कर द्वारा एच0टी0 मीडिया, प्लॉट नं. 8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा-9 उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं जी. एफ. 5/115, गली नं. 5 संत निरंकारी कालोनी, दिल्ली-110009 से प्रकाशित । संपादकः महिमा मक्कर, RNI No. DELHI/2019/77252, संपर्क 011-43563154

विज्ञापन एवं वार्षिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिस के पते पर सम्पर्क करें या फिर इन नम्बरों - 9667793987 या 9667793985 पर बात करें या इस पर media@bharatshri.com ईमेल करें।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

आयुर्वेद क्या हैं?

महत्व, इतिहास और फायदे

आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वस्थ जीवन की दिशा दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता था। आजकल के तेज जीवनशैली में, हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखने के लिए आयुर्वेदिक तरीकों की आवश्यकता है। इससे हम न केवल रोगों को दूर रख सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं।

आयुर्वेद के मूल सिद्धांत क्या हैं?

आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है कि त्रिदोष - वात, पित्त, और कफ, हमारे शरीर के नियंत्रित करते हैं । ये तीनों दोष हमारे शरीर में संतुलन की स्थिति को दर्शाते हैं और इनका संतुलित रहना हमें स्वस्थ रखता है। जब इन दोषों में संतुलन बिगड़ जाता है, तो यह हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते है और बिमारियों का कारण बनते हैं।

आयुर्वेद में यह माना जाता है कि प्रकृति में पांच तत्व होते हैं - पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, और आकाश। वात, पित्त, और कफ इन पांच तत्वों के मिश्रण से बने हैं । वात वायु और आकाश से बना है, पित्त अग्नि और जल से बना है, और कफ पृथ्वी और जल से बना है। आयुर्वेद में त्रिदोषों को संतुलित रखने के लिए विभिन्न उपायों का उल्लेख किया गया है। सेहतमंद जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम अपने आहार, व्यायाम, और ध्यान को संतुलित रखें, ताकि हमारे दोष संतुलित रहें और हम स्वस्थ रहें।

आयुर्वेद का महत्व

आयुर्वेद पांच हजार साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है । इसमें जड़ी बूटि सहित अन्य प्राकृतिक चीजों से उत्पाद, दवा और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इनके इस्तेमाल से जीवन सुखी, तनाव मुक्त और रोग मुक्त बनता है। बीते 75 साल से 'केरल आयुर्वेद' भी आयुर्वेद पर आधारित सामान उप्लब्ध करा लोगों के जीवन को सुगम बनाने का काम कर रहा है।

कंपनी की वेबसाइट भी है, जहां आप ऐसे उत्पाद आसानी से पा सकते हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से प्राकृतिक उत्पादों से बनाया जाता है। आयुर्वेद को 1976 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। यह एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है और त्वचा, बालों, शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। आयुर्वेद केवल जप, योग, उबटन या तेल की मालिश के लिए नहीं है, इसका अध्ययन और अनुसंधान बहुत व्यापक है। इसमें हर स्वास्थ्य समस्या के मूल कारण को समझकर उसके इलाज पर काम किया जाता है। इसी कारण से आयुर्वेद को भारत के अलावा दुनियाभर में महत्वपूर्ण माना जाता है।

आयुर्वेद का इतिहास

आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो कम से कम 5,000 वर्षों से भारत में प्रचलित है। इसका नाम संस्कृत के शब्द "अयुर" (जीवन) और "वेद" (ज्ञान) से आया है। यह प्राचीन चिकित्सा पद्धति पहले ही वेदों और पुराणों में उल्लिखित थी। आजकल आयुर्वेद को योग सहित अन्य पारंपरिक प्रथाओं के साथ एकीकृत किया जाता है। आयुर्वेद की खोज भारत में ही हुई और यहां अधिकांश लोग आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1976 में इसे मान्यता भी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग के अनुसार पश्चिमी दुनिया में भी आयुर्वेद का उपयोग बढ़ रहा है। लेकिन अब भी आयुर्वेद को वैकल्पिक चिकित्सा माना जाता है ।

आयुर्वेद कैसे काम करता है - क्या है तीन दोष?

आयुर्वेद में त्रिदोष - वात-पित्त-कफ का महत्व और इनका हमारे स्वास्थ्य से संबंध:

आयुर्वेद में यह माना जाता है कि अगर इन तीनों दोषों का संतुलन खराब होता है, तो यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, आयुर्वेदिक उपचार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि त्रिदोषों का संतुलन बनाए रखा जाए। आयुर्वेद में, शरीर, मन और चेतना संतुलन बनाए रखने में एक साथ काम करते हैं। शरीर, मन और चेतना की असंतुलित अवस्था (vikruti) विकृति कहा जाता है। कुल मिलाकर, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, चाहे आप किसी भी उम्र के हों।

आयुर्वेदिक दर्शन के अनुसार हमारा शरीर पांच तत्वों (जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु) से मिलकर बना है। वात, पित्त और कफ इन पांच तत्वों के संयोजन और क्रमपरिवर्तन हैं जो सभी निर्माण में मौजूद पैटर्न के रूप में प्रकट होते हैं।

भौतिक शरीर में, वात गति और चाल की सूक्ष्म ऊर्जा है । यह श्वास, हृदय की धड़कन सहित सभी गति विधियों को नियंत्रित करता है। संतुलन में, वात रचनात्मकता और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। संतुलन न होने से, वात भय और चिंता पैदा करता है और जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस का कारण बनता है।

पित्त शरीर की चयापचय प्रणाली के रूप में व्यक्त करता है - आग और पानी से बना है। यह पाचन, अवशोषण, आत्मसात, पोषण, चयापचय और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। संतुलन में, पित्त समझ और बुद्धि को बढ़ावा देता है। संतुलन न होने से, पित्त क्रोध, घृणा और ईर्ष्या पैदा करता है। कफ वह ऊर्जा है जो शरीर की संरचना - हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन - का निर्माण करती है और "गोंद" प्रदान करती है जो कोशिकाओं को एक साथ रखती है, जो पृथ्वी और जल से मिलकर बनती है। यह जोड़ों को चिकनाई देता है, त्वचा को मॉइस्चराइज़ करता है, और प्रतिरक्षा को बनाए रखता है। संतुलन में, कफ को प्यार, शांति और क्षमा के रूप में व्यक्त किया जाता है। संतुलन से बाहर, यह लगाव, लालच और ईर्ष्या की ओर जाता है।

आयुर्वेद के स्वास्थ्य लाभ

स्वस्थ वजन, त्वचा और बाल का रखरखाव

सही वज़न, निखरी त्वचा और घने, खूबसूरत बाल - स्वस्थ आहार और आयुर्वेदिक इलाजों के माध्यम से जीवनशैली में संशोधन करके शरीर से अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद खान-पान में सुधार लाकर एक स्वस्थ वजन को मेन्टेन करने में मदद करता है। ऑर्गेनिक और प्राकृतिक तरीकों से आप स्वस्थ त्वचा पा सकते है। सिर्फ यही नही, संतुलित भोजन, टोनिंग व्यायाम और आयुर्वेदिक पूरक / सप्लीमेंट के मदद से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेग।

आयुर्वेदिक इलाज आपको तनाव से बचने में मदद करता हैं-

योग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मसाज और हर्बल उपचारों का नियमित अभ्यास शरीर को शांत, डिटॉक्सिफाई और कायाकल्प करने में मदद करता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हमारे शरीर में सक्रियता बढ़ती है और कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है। टेंशन और चिंता को दूर रखने के लिए आयुर्वेद में शिरोधारा, अभ्यंग, शिरोभ्यंग, और पादाभ्यंग जैसे व्यायामों की सलाह दिया जाता है।

जलन और सूजन में मदद करें

उचित आहार की कमी, अस्वास्थ्यकर भोजन, दिनचर्या, अपर्याप्त नींद, अनियमित नींद पैटर्न और खराब पाचन से इन्फ्लेम्शन हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल रोगों, कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याओं, फुफ्फुसीय रोगों, गठिया, और कई अन्य रोगों का मूल कारण इन्फ्लेम्शन से शुरू होता है। जैसे-जैसे आप अपने दोष के अनुसार खाना शुरू करते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होने लगता है। सही समय पर कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन रक्त और पाचन तंत्र में विषाक्त पदार्थों को कम करता है। जिससे जीवन शक्ति और उच्च ऊर्जा प्राप्त होता है और साथ ही साथ मूड स्विंग्स और सुस्ती को कम करने में मदद करता है।

शरीर का शुद्धिकरण

आयुर्वेद में पंचकर्म में एनीमा, रक्तमोक्ष,जैसे पंचकर्म के माध्यम से शारीरिक विषाक्त पदार्थों को शरीर से बहार निकलता है ।

संत सच्चल जी: प्रेम की दिव्य मस्ती

प्रेम की उच्चतम स्थिति

प्रेम की दिव्यता का वर्णन केवल एक उच्च कोटि का प्रेमी ही अपनी प्रेमानुभूति के प्रकाश में थोड़ा-बहुत कर सकता है। प्रेम की सबसे पवित्र स्थिति वह है जहां प्रेमी, प्रियतम और प्रेम तीनों एकाकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रहने वाला प्राणी धन्य है। सिंध के विख्यात और दयामय संत सच्चल उच्च कोटि के प्रेमी थे। अपने प्रेमास्पद के रूप, सौंदर्य और माधुर्य के मद से वे हमेशा मस्त रहते थे। सूफी प्रेम साधना की उच्च भूमिका में रमण करना उनका सहज स्वभाव बन गया था। परमात्मा अल्लाह का प्रेम उनका जीवन-सर्वस्व था। लोगों को भगवत प्रेम का रसास्वादन कराने के लिए ही उन्होंने कृपापूर्वक पृथ्वी पर जन्म लिया था। उनका पथ प्रेम और सत्य का पथ था। उन्होंने निस्संकोच कहा कि भीतर-बाहर, हृदय में सब जगह वही प्रभु प्रेमास्पद हैं। मुझमें, तुममें और उसमें वही बोलते हैं।

सिंध प्रदेश ने अनेक सिद्ध सूफी संतों को जन्म दिया है। 18वीं शताब्दी के सूफी संत कवि शाह लतीफ ने सिंध में भगवत प्रेम की मंदाकिनी प्रवाहित की थी। इसी तरह प्रसिद्ध सूफी कवि बेदिल के पुत्र बेकस ने अपनी प्रेम काव्य-धारा से असंख्य प्राणियों को तृप्त करने का पवित्र पुण्य कमाया। सिंध के प्रेम-साहित्य की परंपरा की अविच्छिन्न कड़ी संत सच्चल हैं, जिनकी संगीतमयी अमृत वाणी का सिंदूर चिरंतन और सनातन है। सूफी संत सच्चल की वाणी ने घोषणा की:

"जागो और खोजो, तुम
प्रियतम को अपने भीतर पाओगे।"

वे वास्तव में फकीर थे। उन्होंने परमात्मा के प्रेम राज्य की प्राप्ति के लिए दैन्य का वरण किया था। वे कहा करते थे कि तुम मुझे फकीर के वेश में देखते हो, लेकिन जब तुम मेरी आंतरिक सत्ता समझोगे, तब जानोगे कि मैं भिखारी नहीं, राजाधिराज हूं। दरवेश सच्चल ने दिव्य जीवन, भगवत जीवन को ही परम श्रेयस्कर समझा। वे प्रेम की दिव्य उन्माद स्थिति, मस्ती में सदा झूमते रहते थे।

जन्म और बाल्यकाल

फकीर सच्चल का जन्म सिंध प्रदेश के खैरपुर राज्य के दारजन गांव में संवत 1796 में हुआ था। दारजन में अब भी उनका स्मारक है। उनका बचपन का नाम अब्दुल वहाब था। उनकी अल्पावस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया। वे अपने चाचा पीर अब्दुल हक के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त करने लगे। अब्दुल हक सूफी विचारधारा के पवित्र व्यक्ति थे। वे सूफी साधना की चिश्ती पद्धति से प्रभावित थे। 12वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के नाम से यह परंपरा प्रसिद्ध थी। यह स्वाभाविक था कि अब्दुल हक के पवित्र प्रेममय जीवन का अब्दुल वहाब, यानी सच्चल पर प्रभाव पड़ता।

एक दिन दारजन में उस समय के सिद्ध सूफी संत शाह लतीफ का आगमन हुआ। वे सच्चल के पितामह से मिलने आए थे। सच्चल की अवस्था इस समय केवल 7 साल की थी। शाह लतीफ उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए और कहा कि मेरे बच्चे, तुम सत्य का रहस्योद्घाटन करोगे। जब सच्चल पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजे गए, तो उन्होंने 'अलीफ' के उच्चारण के बाद दूसरा अक्षर 'बे' कहना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि 'अलीफ' अल्लाह का प्रतीक है। अल्लाह अद्वितीय है। उनके बाद दूसरे अक्षर का उच्चारण नितांत अवैध और मर्यादा के विरुद्ध है। ऐसा करना उनके अस्तित्व को अस्वीकार करना है। सच्चल की प्रतिभा असाधारण थी।

आध्यात्मिक प्रभाव और साधना

सच्चल फकीर के चरित्र-विकास पर चिश्ती परंपरा के सूफी संत फकीर मुकमलुद्दीन का बड़ा प्रभाव पड़ा था। वे जिस समय सिंध का परिभ्रमण कर रहे थे, सच्चल फकीर अपने चाचा की आज्ञा से उनसे मिलने गए। फकीर एक कमजोर घोड़ी की पीठ पर थे। सच्चल फकीर को उन्होंने घोड़ी प्रेम-उपहार रूप में प्रदान की और आध्यात्मिक पथ में बढ़ने का आशीर्वाद दिया।

यद्यपि अरबी और फारसी का सच्चल ने अच्छी तरह अध्ययन किया था, तथापि अल्लाह का प्रेम ही उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्यय था। वे कहा करते थे कि जीवन में ज्ञान और प्रेम को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रेम की ज्योति सच्चे व्यक्ति में ही पैदा होती है। उनके लिए प्रेम ही उपास्य था। वे वचन-भाषण नहीं, शांति-मौन को बहुत बड़ी शक्ति स्वीकार करते थे।

उनकी साधना का प्राण संगीत था। सच्चल फकीर के रोम-रोम में संगीत समाया हुआ था। एक समय की बात है, वे बीमार थे। बीमारी असाध्य थी। कुछ नवयुवतियां उनका दर्शन करने आईं। वे संगीत में निपुण थीं। उन्होंने गीत गाए। गीत के माधुर्य से सच्चल का स्वास्थ्य लौट आया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। सच्चल स्वयं उच्च कोटि के प्रेम-गायक थे। वे अपने सरस पदों को मस्ती में झूम-झूम कर गाया करते थे। अपने प्रेमभरे मधुर पद-गान से उन्होंने असंख्य प्राणियों को परमात्मा का प्रेमी बना दिया। सच्चल फकीर का एक गीत है:

"साकी, मुझे अगूरी शराब की आवश्यकता नहीं है। मुझे (समस्त जीवों से) अभिन्नता की शराब चाहिये और भिन्नता की भावना से मुझे मुक्ति चाहिये।"

सच्चल फकीर ने अपने बाल्यकाल के संरक्षक और शिक्षक-मुरशिद अब्दुल हक से सत्य-प्रेम और आत्मज्ञान की शिक्षा पाई थी। अब्दुल हक ने सीख दी थी कि सच्ची शिक्षा का संबंध तो हृदय से है। अब्दुल हक स्वयं एक उन्मुक्त आत्मा थे। सच्चल फकीर उनका बड़ा आदर करते थे। सच्चल फकीर बड़ी सादगी से रहते थे और साधारण भोजन करते थे। अल्लाह का नाम ही उनके लिए मधुमय पेय था। उनकी वाणी है:

"मेरे मुरशिद ने एक दिन मुझसे कहा
संसार के लोगों का संबंध त्याग दो, अल्लाह
का नाम स्मरण करो और शेष भूल जाओ।"

वे मरुस्थलीय वातावरण में अपने समय का अधिकांश शांतिपूर्ण भगवत चिंतन में लगाते थे। वे कहा करते थे कि समस्त रूपों में (अल्लाह) एक के ही सौंदर्य का दर्शन करो, और कुछ देखना पाप है। वे परमात्मा की सत्य और सौंदर्य-रूप में उपासना करते थे। वे प्रेम के सौंदर्य राज्य में संगीत के माध्यम से प्रवेश करते थे। सच्चल फकीर प्रसिद्ध सूफी संत फरीद अल-दीन अत्तार की विचार-धारा से बहुत प्रभावित थे। वे 11वीं शताब्दी में थे। उनकी अच्छे सूफी संतों में गणना है। सच्चल फकीर उनको इस्लामी जगत का महान संत मानते थे। उन्होंने परमात्मा के पथ पर चलने के प्रेममय गीत गाए।

प्रेम की मस्ती और शिक्षाएं

सच्चल फकीर एकांत और मौन को अपनी प्रेममयी भगवत साधना का प्राण मानते थे। वे प्रायः दरवाजा बंद कर अधिक समय तक परमात्मा का चिंतन किया करते थे। वे रात-रात भर जागते रह जाते थे और उनकी आंखों में प्रेमाश्रु निरंतर उमड़ता रहता था। उनके चेहरे पर दिव्य सौंदर्य झलक उठता था। जब वे एकतारा लेकर प्रेम-संगीत गाने लगते थे और उनके सुंदर केश हवा में लहराने लगते थे, तब असंख्य प्राणी भगवत प्रेम में निमग्न होकर उनके चरण कमलों में आत्मार्पण कर देते थे। वे मस्ती में गाया करते थे कि अपनी विषय-कामना का त्याग करो, अपने आप को मिटा देने की चिंता करो, अपने आप को उसी पर चढ़ कर जला दो। यह 'फना' का सिद्धांत है। अपने आप को मिटा देने पर ही प्रियतम की सम्पूर्ण प्राप्ति होती है।

सच्चे सूफी की तरह दरवेश सच्चल ने प्रियतम परमात्मा को भीतर, बाहर और हृदय में सर्वत्र देखा। उन्होंने कहा कि मुझमें, तुममें, उसमें, सबमें उसी एक की सत्ता कार्यशील है और उनका प्रत्येक कार्य यज्ञ है। सच्चल फकीर ने जीवमात्र के प्रति मैत्री, एकता और अभिन्नता की सीख दी। वे जाति, वर्ग, मतमतांतर से अतीत और निरपेक्ष होने पर बहुत जोर देते थे। एक ही सत्य सबमें समान रूप से परिव्याप्त है। उसी की अनुभूति जीवन में उतारनी चाहिए। वे रहस्यवादी थे। वे अपने जीवन को सदा पूर्ण प्रेममय देखना चाहते थे। उन्होंने सनातन भगवत प्रेम की सीख दी कि मैं अपने आप को किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत में नहीं जकड़ना चाहता हूं और न उन्हें स्वीकार ही करता हूं। मुल्ला लोगों ने उनके प्रति विद्रोह किया। सच्चल फकीर ने समझाया:

"मैं आप लोगों में से प्रत्येक से कहता हूं कि आप पहले अपने आप को जानिए। इसके उपरांत प्रेम के पथ पर चलिए। मेरे मुरशिद ने मुझे इस प्रेम-पथ पर चलना सिखाया है।"

वे कहा करते थे कि यदि प्रियतम की खोज है तो वे हृदय-मंदिर में ही निवास करते हैं। सच्चल फकीर अद्भुत प्रेमी थे। संत सच्चल ने आजीवन दिव्य प्रेम का ही गान गाया।

समाधि और विरासत

संत सच्चल ने संवत 1889 में रमजान की चौदहवीं तिथि को असार संसार का त्याग कर प्रेमलोक की यात्रा की। इस समय उनकी अवस्था 90 साल की थी। दारजन में उनकी समाधि मानवता को दिव्य भगवत प्रेम का संदेश देती हुई खड़ी है। जिसके दर्शन मात्र से रोम-रोम में परमानंद का मधुर सागर उमड़ पड़ता है। सच्चल फकीर पहुंचे हुए संत थे। सिंध की पवित्र भूमि धन्य है जिसने सच्चल फकीर का स्पर्श पाया।

रचनाएं

समय-समय पर निकले पदबद्ध प्रेमोद्गार ही उनकी अमरकृति के रूप में सुरक्षित हैं।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

एपस्टीन फाइल्स से नॉर्वे तक हड़कंप

क्राउन प्रिंसेस मेटे-मारिट और यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के रिश्तों पर उठा बड़ा सवाल

@ आनंद मीणा

अमेरिका में जारी हुईं कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी नई फाइलों ने अब यूरोप के शाही गलियारों तक हलचल मचा दी है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मारिट और एपस्टीन के बीच कथित निजी रिश्तों के सामने आने के बाद न सिर्फ नॉर्वे, बल्कि पूरी दुनिया में इस मामले पर बहस तेज हो गई है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा 30 जनवरी को सार्वजनिक की गई एपस्टीन फाइल्स में 'प्रिंसेस' शब्द का एक हजार से अधिक बार जिक्र होने से यह विवाद और गहरा गया है।

एपस्टीन फाइल्स में क्या सामने आया?

नॉर्वे के प्रतिष्ठित अखबार VG की रिपोर्ट के अनुसार, जारी किए गए दस्तावेज़ों में 2011 से 2014 के बीच मेटे-मारिट और जेफ्री एपस्टीन के बीच हुए कई ईमेल शामिल हैं। इन ईमेल्स से पता चलता है कि दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक संपर्क नहीं, बल्कि लंबे समय तक निजी संवाद और नजदीकी संबंध रहे।ईमेल्स में बातचीत का लहजा दोस्ताना ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर फ्लर्टी भी बताया गया है। यही बात इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना देती है, क्योंकि यह संपर्क उस समय का है जब एपस्टीन पहले ही नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका था।

'पेरिस अफेयर' वाला मेल और विवाद

फाइल्स में शामिल एक ईमेल में एपस्टीन ने मेटे-मारिट से कहा था कि वह शादी करना चाहता है और पत्नी की तलाश में पेरिस आया है। उसने मज़ाकिया और फ्लर्टी अंदाज़ में लिखा कि पेरिस अवैध संबंधों और अफेयर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर वफादार पत्नी चाहिए तो स्कैंडिनेवियाई महिलाएं सबसे बेहतर होती हैं।इस पर मेटे-मारिट ने जवाब दिया था,"मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में पत्नी की तलाश कर रहे हैं।"यह संवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि मेटे-मारिट स्वयं स्कैंडिनेवियाई महिला हैं और नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस हैं।

निजी ईमेल्स ने बढ़ाई मुश्किलें

कुछ ईमेल्स में मेटे-मारिट ने एपस्टीन की बातों को "गुदगुदाने वाला" बताया। एक मेल में उन्होंने एपस्टीन से पूछा कि क्या अपने 15 वर्षीय बेटे के कमरे में सर्फबोर्ड के साथ दो न्यूड लड़कियों की तस्वीर लगाना ठीक रहेगा। वहीं अन्य मेल्स में उन्होंने एपस्टीन को आकर्षक, स्वीटहार्ट और सॉफ्ट हार्टेड जैसे शब्दों से संबोधित किया।इन ईमेल्स के सार्वजनिक होने के बाद नॉर्वे में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठने लगे कि आखिर एक शाही सदस्य इस तरह के व्यक्ति से इतनी नजदीकी कैसे रख सकती हैं।

तीन बार हुई मुलाकातें, फ्लोरिडा में चार दिन

दस्तावेज़ों से यह भी सामने आया है कि मेटे-मारिट और एपस्टीन केवल ईमेल तक सीमित नहीं थे। 2011 से 2013 के बीच दोनों की तीन बार मुलाकात हुई। ये मुलाकातें ओस्लो, न्यूयॉर्क और कैरिबियन में हुईं।सबसे ज्यादा विवाद 2013 की उस यात्रा को लेकर है, जब मेटे-मारिट फ्लोरिडा में एपस्टीन के घर चार दिन तक रुकीं। हालांकि, शाही बयान में कहा गया है कि उस दौरान एपस्टीन घर पर मौजूद नहीं था।एक अन्य ईमेल में यह भी सामने आया कि जब मेटे-मारिट बीमार थीं, तब एपस्टीन ने उन्हें फूल भेजे थे। जवाब में मेटे-मारिट ने 'लव, MM' लिखकर धन्यवाद दिया था।

दोषी ठहराए जाने के बाद भी संपर्क क्यों?

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यही है कि यह संपर्क उस समय का है जब एपस्टीन 2008 में नाबालिग से वेश्यावृत्ति के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका था।2011 के एक ईमेल में मेटे-मारिट ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने एपस्टीन के खिलाफ चल रहे मुकदमे के बारे में गूगल पर पढ़ा था और उन्हें यह अच्छा नहीं लगा, इसके बावजूद उन्होंने संपर्क बनाए रखा।यही बिंदु आलोचकों के निशाने पर है।

मेटे-मारिट की सफाई और माफी

विवाद बढ़ने के बाद शनिवार को नॉर्वे के शाही परिवार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया। इसमें मेटे-मारिट ने एपस्टीन से अपने संबंधों को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।उन्होंने कहा कि उन्होंने 2014 में एपस्टीन से संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि वह उनका इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए करना चाहता है।मेटे-मारिट ने यह भी कहा कि वे एपस्टीन केस की सभी पीड़िताओं के साथ गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त करती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एपस्टीन की पृष्ठभूमि को समय रहते ठीक से न समझ पाना उनकी अपनी गलती थी।

शाही परिवार पर असर

नॉर्वे का शाही परिवार आमतौर पर पारदर्शिता और सादगी के लिए जाना जाता है। ऐसे में यह विवाद उनके लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है। हालांकि अब तक नॉर्वे के राजा हाराल्ड पंचम या क्राउन प्रिंस हाकॉन की ओर से कोई सीधा राजनीतिक बयान नहीं आया है, लेकिन मामला शाही प्रतिष्ठा से जुड़ चुका है।इस बीच मेटे-मारिट के बड़े बेटे मारियस होइबी को लेकर भी चर्चा हुई है। मारियस मेटे-मारिट के विवाह से पहले के रिश्ते से जन्मे थे, इसलिए उन्हें कभी शाही उपाधि नहीं दी गई।रॉयल फैमिली पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मारियस शाही परिवार का औपचारिक सदस्य नहीं हैं और सिंहासन के उत्तराधिकारी भी नहीं हैं। इससे शाही परिवार इस विवाद के प्रभाव को सीमित रखने की कोशिश करता दिख रहा है।

सामान्य परिवार से शाही महल तक का सफर

मेटे-मारिट की कहानी अपने आप में असाधारण रही है। उनका जन्म 19 अगस्त 1973 को नॉर्वे के क्रिस्टियानसैंड शहर में एक सामान्य परिवार में हुआ। पिता पत्रकार थे और मां बैंक क्लर्क।1997 में वे सिंगल मदर बनीं और अपने बेटे की परवरिश के लिए खुद काम किया। 2000 में उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस हाकॉन से हुई। 2001 में शादी के बाद वे नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस बनीं।शादी के समय उनके अतीत को लेकर भी विवाद हुआ था, जिसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगी थी।

अपराध की पूरी कहानी

जेफ्री एपस्टीन केस की शुरुआत 2005 में हुई, जब फ्लोरिडा में एक 14 वर्षीय लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि यह कोई अकेला मामला नहीं था। धीरे-धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों ने उस पर यौन शोषण के आरोप लगाए। एपस्टीन अपने आलीशान घरों, निजी जेट 'लोलिता एक्सप्रेस' और हाई-प्रोफाइल पार्टियों के लिए जाना जाता था। उसकी सहयोगी गिस्लीन मैक्सवेल लड़कियों को फंसाने में मदद करती थी।2008 में रसूख के चलते उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली। 2019 में दोबारा गिरफ्तार हुआ, लेकिन मुकदमे से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। गिस्लीन मैक्सवेल को 2021 में दोषी ठहराकर 20 साल की सजा दी गई।

सवाल जो अब भी बाकी हैं

मेटे-मारिट और एपस्टीन के रिश्तों पर सामने आए दस्तावेज़ों ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक गलत आकलन था, या शाही जिम्मेदारी में गंभीर चूक? क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को अपने निजी रिश्तों को लेकर ज्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए? फिलहाल इतना तय है कि एपस्टीन फाइल्स की परतें खुलने के साथ यह मामला अभी थमा नहीं है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस से जुड़ा यह विवाद आने वाले दिनों में और भी राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दे सकता है।

वृंदावन में भक्ति, साधना और सेवा का महासंगम

श्री राधा कृष्ण स्वर्ण मंदिर धाम में भव्य ज्योति दिवस का अलौकिक आयोजन

@ भारतश्री ब्यूरो

वृंदावन की पावन धरा एक बार फिर भक्ति, श्रद्धा और सनातन चेतना के अद्भुत साक्षात्कार की साक्षी बनी, जब श्री राधा कृष्ण स्वर्ण मंदिर धाम में ज्योति दिवस का भव्य और दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक उत्सव था, बल्कि सनातन परंपरा, गुरु-शिष्य परंपरा और मानव कल्याण के संकल्प का जीवंत उदाहरण भी बना। देश और दुनिया के कोने-कोने से आए लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बना दिया।

श्रद्धालुओं का वर्षों का प्रतीक्षित पर्व

यह आयोजन प्रभु कृपा दुख निवारण समागम के रूप में विख्यात है, जिसका श्रद्धालु वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं। इसका कारण केवल इसका भव्य स्वरूप नहीं, बल्कि इसका आध्यात्मिक उद्देश्य है। यह समागम जगतगुरु महाब्रह्मर्षि श्री स्वामी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस पावन अवसर पर गुरु कृपा से जीवन के अनेक कष्टों का निवारण होता है और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है।

साधु-संतों की दिव्य उपस्थिति

ज्योति दिवस के अवसर पर काशी, मथुरा, हरिद्वार, वृंदावन, अयोध्या सहित देश-विदेश के अनेक आध्यात्मिक केंद्रों से साधु-संतों का आगमन हुआ। इन दिव्य विभूतियों की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। हर ओर मंत्रोच्चार, कीर्तन और वैदिक परंपराओं की गूंज सुनाई दे रही थी। विशेष रूप से गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्ध आचार्य महाराज की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। उन्होंने जगतगुरु महा ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके दीर्घायु होने की कामना की। अनिरुद्ध आचार्य महाराज ने जगतगुरु के संकल्पों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे दिव्य, निस्वार्थ और राष्ट्र-धर्म के लिए समर्पित संत इस युग में अत्यंत दुर्लभ हैं।

समागम को मिली आध्यात्मिक ऊंचाई

इस आयोजन में विशेश्वर आनंद हरि चेतनानंद, महामंडलेश्वर नवल गिरी जी महाराज, बांके बिहारी मंदिर के मुख्य पुजारी सहित अनेक प्रतिष्ठित संत-महात्मा उपस्थित रहे। इन सभी की उपस्थिति ने समागम को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की। संतों के सान्निध्य में श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं देवभूमि धरती पर उतर आई हो।

हवन और वैदिक अनुष्ठान

समागम से पूर्व भव्य हवन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रों के उच्चारण और अग्नि में आहुति के साथ वातावरण शुद्ध और पवित्र हो उठा। संतों ने संगत को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित किया और जीवन में धर्म, संयम और सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला।

ब्रह्मस्वरूपिणी ऋतु खुशबू जी के वचन

इसके उपरांत ब्रह्म स्वरूपिणी ऋतु खुशबू जी ने संगत को आशीर्वचन प्रदान किए। उनके वक्तव्यों ने विशेष रूप से युवा वर्ग को गहराई से प्रभावित किया। उनके विचारों में सनातन धर्म की मौलिक व्याख्या, जीवन मूल्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की स्पष्ट झलक दिखाई दी। युवाओं में उन्हें सुनने की विशेष उत्सुकता देखी गई। श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि ब्रह्म स्वरूपिणी जी के वचनों को सुनकर यह समझ में आता है कि सनातन धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण और संतुलित पद्धति है। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार आज के समय में सनातन धर्म की रक्षा विचार, आचरण और सेवा के माध्यम से की जा सकती है।

संगीत और साधना का अद्भुत संगम

गुरु मां जी द्वारा प्रस्तुत किया गया एक भावपूर्ण संगीत पूरे पंडाल को मंत्रमुग्ध कर गया। भक्ति रस से सराबोर इस प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को आत्मिक आनंद की अनुभूति कराई। संगीत, साधना और भक्ति का यह संगम लंबे समय तक स्मरणीय रहेगा। समागम के अंतिम चरण में जगतगुरु महा ब्रह्मर्षि शिवकुमार स्वामी जी ने बीज मंत्र का पाठ कराया। इस मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बरसाई और जीवन के संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गुरु कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है।

स्वास्थ्य शिविर बना मानवता का उदाहरण

इस भव्य समागम से पहले एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। देशभर से आए अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हजारों लोगों की जांच कर उन्हें परामर्श और उपचार प्रदान किया। विशेष रूप से डैंड्रफ और यूटीआई जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अलग शिविर लगाए गए। यह सेवा कार्य आयोजन का मानवीय और सामाजिक पक्ष उजागर करता है। ज्योति दिवस का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह सनातन संस्कृति, गुरु परंपरा और सामाजिक सेवा का जीवंत उत्सव बन गया। वृंदावन की पावन भूमि पर आयोजित यह समागम श्रद्धालुओं के हृदय में आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर गया।

श्रद्धा, सेवा और संकल्प का संदेश

इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि जब भक्ति के साथ सेवा और संकल्प जुड़ जाते हैं, तो वह केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहता, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बन जाता है। श्री राधा कृष्ण स्वर्ण मंदिर धाम में आयोजित ज्योति दिवस आने वाले वर्षों तक श्रद्धालुओं के मन में स्मृति और प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगा। यह समागम इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म आज भी उतना ही प्रासंगिक, जीवंत और मार्गदर्शक है, जितना वह युगों पहले था।

वायरल होने का सपना, कमाई का भ्रम

कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी का सच

@ मनीष पांडेय

कंटेंट क्रिएटर भारत में यह शब्द अब सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक सपना बन चुका है। खासकर जेन ज़ी की बातचीत में यह टर्म आम है। फॉलोअर्स कितने हैं, रील वायरल हुई या नहीं, लाइक्स कितने आए,आज की डिजिटल पीढ़ी इन्हीं सवालों के बीच जी रही है। मोबाइल की छह इंच की स्क्रीन पर शोहरत और पहचान पाने के लिए देश में 20 से 25 लाख लोग दिन-रात कंटेंट बना रहे हैं।लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक सवाल लगातार खड़ा है। कमाई कितने लोगों की हो रही है? क्या हर कंटेंट क्रिएटर पैसा कमा रहा है? और आखिर इस पूरी क्रिएटर इकोनॉमी का असली सच क्या है?

जब बेरोज़गार कहलाते थे क्रिएटर

आज से करीब 15 साल पहले जब भारत में कुछ युवाओं ने यूट्यूब, ब्लॉग और सोशल मीडिया के ज़रिए कंटेंट बनाना शुरू किया, तब हालात बिल्कुल अलग थे। उस दौर में न तो ब्रैंड डील्स थीं, न स्पॉन्सरशिप और न ही यह समझ कि इंटरनेट भी रोज़गार दे सकता है। कंटेंट बनाने वाले युवाओं को अक्सर उनके पड़ोसी, रिश्तेदार और समाज 'बेरोज़गार' कहकर तंज कसते थे।लेकिन वक्त बदला। इंटरनेट सस्ता हुआ, स्मार्टफोन हर हाथ में आया और सोशल मीडिया ने आम लोगों को भी मंच दे दिया। आज वही कंटेंट क्रिएशन एक उभरती हुई इंडस्ट्री बन चुका है।

अरबों डॉलर का खेल

इसी साल मई में मुंबई में हुए वेव्स समिट में जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने सबका ध्यान खींचा। बताया गया कि भारत के डिजिटल क्रिएटर्स हर साल करीब 350 अरब डॉलर की कस्टमर स्पेंडिंग को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान है कि अगले पांच साल में यह आंकड़ा एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा।यानी भारत की कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी करीब एक लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक जा सकती है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक इंजन बनता जा रहा है।सरकार ने भी इस बदलाव को गंभीरता से लिया है। मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ डॉलर का फंड तैयार किया जाएगा। साफ है कि सरकार भी मान रही है कि मोबाइल स्क्रीन पर बनने वाला कंटेंट अब देश की बड़ी सेल्स फोर्स में बदल चुका है।

कितने लोग मैदान में हैं

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 20 से 25 लाख ऐसे एक्टिव डिजिटल क्रिएटर हैं, जिनके कम से कम 1000 फॉलोअर्स हैं और जो नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट पोस्ट करते हैं। सस्ते डेटा और तेज़ इंटरनेट ने इस रेस को और तेज़ कर दिया है।खासकर जेन ज़ी के बीच यह सोच आम हो गई है कि कॉलेज, नौकरी या पारंपरिक करियर से बेहतर है कि फोन उठाओ और कंटेंट बनाकर वायरल हो जाओ।

कमाई का कड़वा सच

लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट इस चमकदार दुनिया का असली सच सामने रखती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में सिर्फ 8 से 10 प्रतिशत कंटेंट क्रिएटर ही अपने कंटेंट से ढंग की कमाई कर पा रहे हैं।यानी 20 से 25 लाख एक्टिव क्रिएटर्स में से सिर्फ 2 से ढाई लाख लोग ही ऐसे हैं, जिनकी कमाई सोशल मीडिया से हो रही है। बाकी के 90 से 92 प्रतिशत क्रिएटर या तो बहुत मामूली कमाते हैं या फिर उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत सोशल मीडिया नहीं है।यह आंकड़ा उन लाखों युवाओं के लिए आंख खोलने वाला है, जो सिर्फ वायरल होने को सफलता मान लेते हैं।

कमाई आती कहां से है

जो क्रिएटर सफल हैं, उनकी कमाई के रास्ते भी एक जैसे नहीं होते। टॉप क्रिएटर्स बड़े ब्रैंड्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। उनके पास बड़ी ऑडियंस होती है, इसलिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सेवाओं को प्रमोट करने के लिए उन्हें मोटी रकम देती हैं।इसके अलावा प्लेटफॉर्म एड रेवेन्यू, ब्रैंड स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, सब्सक्रिप्शन मॉडल और प्रीमियम कंटेंट भी कमाई के बड़े स्रोत हैं। कुछ क्रिएटर अपने कोर्स, मर्चेंडाइज और एक्सक्लूसिव वीडियो के ज़रिए भी पैसा कमाते हैं। लेकिन यह सब हर किसी के हिस्से में नहीं आता।

असली मुनाफा किसका यह बात सच है कि भारत में कई कंटेंट क्रिएटर करोड़पति बने हैं। उनके वीडियो, रील्स और चैनल लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन

इस पूरे खेल के असली विजेता कौन हैं?बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में यूट्यूब के भारतीय ऑपरेशन की आय करीब 14,300 करोड़ रुपये रही। वहीं फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा का टर्नओवर भी हजारों करोड़ रुपये का रहा।यानी जिन प्लेटफॉर्म्स पर क्रिएटर मेहनत करते हैं, असली मुनाफा वही प्लेटफॉर्म्स कमा रहे हैं। कंटेंट क्रिएटर इस सिस्टम की रीढ़ जरूर हैं, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा कंपनियों के खाते में जाता है।

कंपटीशन और मानसिक दबाव

कंटेंट क्रिएशन की दुनिया जितनी ग्लैमरस दिखती है, उतनी ही कठिन भी है। यहां कंपटीशन बेहद ज्यादा है। हर दिन हजारों नए वीडियो अपलोड होते हैं। हर कोई वायरल होना चाहता है।इस दौड़ में तुलना और असफलता का मानसिक दबाव भी बहुत बढ़ जाता है। कम लाइक्स, कम व्यूज और घटते फॉलोअर्स कई युवाओं को तनाव और निराशा की ओर ले जाते हैं। कई बार यह दबाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है।

सपना और हकीकत के बीच

इसमें कोई शक नहीं कि कंटेंट क्रिएशन एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। इसमें अवसर हैं, पहचान है और कमाई की संभावना भी है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यहां सफलता पाना आसान नहीं।हर वायरल वीडियो के पीछे हजारों असफल कोशिशें छुपी होती हैं। हर सफल क्रिएटर के पीछे लाखों ऐसे लोग हैं, जिनकी मेहनत अभी रंग नहीं लाई।

सोच-समझकर चुनना होगा रास्ता

कंटेंट क्रिएटर बनना गलत नहीं है, लेकिन इसे जादुई शॉर्टकट समझना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह भी एक पेशा है, जिसमें स्किल, धैर्य, निरंतरता और समझदारी चाहिए।छह इंच की स्क्रीन बड़े सपने दिखाती है, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है। कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी का सच यही है। चमक बहुत है, मगर हर चमक सोना नहीं होती।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

पीरियड्स- चुप्पी की कीमत और अधिकार की दस्तक

जब एक प्राकृतिक प्रक्रिया शर्म बना दी गई और शिक्षा उसका सबसे बड़ा शिकार बन गई

@ सौम्या चौबे

आज भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि हर लड़की के शरीर में होने वाली एक पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया को समाज ने इतना रहस्यमय, डरावना और शर्मनाक क्यों बना दिया। पीरियड्स न तो कोई बीमारी हैं, न कोई गंदगी। यह जीवन की निरंतरता से जुड़ी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इसके बावजूद भारतीय समाज में इसे आज भी फुसफुसाहट, परदे और पाबंदियों के साथ जोड़ा जाता है। नतीजा यह है कि पीरियड्स सिर्फ शरीर का मामला नहीं रहे, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़े एक बड़े सामाजिक संकट में बदल चुके हैं।

आंकड़े जो समाज का आईना दिखाते हैं

भारत में आज 35 करोड़ से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें नियमित रूप से पीरियड्स आते हैं। यह संख्या किसी छोटे देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इसके बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति बेहद चिंताजनक है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इनमें से सिर्फ 12.6 करोड़ महिलाएं ही सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। यानी महज 36 प्रतिशत। बाकी बड़ी आबादी आज भी या तो कपड़े, राख, भूसा, कागज या फिर ऐसे असुरक्षित तरीकों पर निर्भर है, जिनका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 बताता है कि शहरों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। शहरी इलाकों में करीब 90 प्रतिशत लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित साधनों का उपयोग करती हैं। लेकिन गांवों में तस्वीर बिल्कुल उलटी है। ग्रामीण भारत में आज भी केवल 36 प्रतिशत लड़कियां ही सुरक्षित तरीके अपनाती हैं। बाकी 64 प्रतिशत या तो जानकारी के अभाव में या संसाधनों की कमी के कारण जोखिम उठाने को मजबूर हैं।

सबसे डरावनी सच्चाई: जानकारी का अभाव

इन आंकड़ों से भी ज्यादा डराने वाली एक और सच्चाई है। भारत में 71 प्रतिशत लड़कियों को पहली बार पीरियड्स आने से पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। न घर में, न स्कूल में, न समाज में। जब पहली बार शरीर में बदलाव होता है तो डर, शर्म और भ्रम ही उनके हिस्से आता है। कई लड़कियां इसे बीमारी समझ लेती हैं, कई खुद को गंदा मानने लगती हैं। यही वह मोड़ है जहां से पीरियड्स को लेकर मानसिक बोझ और सामाजिक दूरी की शुरुआत होती है।

शिक्षा पर सबसे गहरी चोट

2014 में डासरा की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 2.3 करोड़ लड़कियां सिर्फ पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं के कारण स्कूल छोड़ देती थीं। वजहें वही पुरानी थीं—पैड का खर्च, स्कूल में टॉयलेट की कमी, पानी और डिस्पोजल की व्यवस्था न होना और सबसे ऊपर सामाजिक शर्म।दस साल बाद, यानी 2024 में जब दोबारा इस स्थिति का आकलन किया गया तो उम्मीद थी कि तस्वीर बदली होगी। लेकिन नतीजे फिर भी निराशाजनक रहे। नई स्टडी में सामने आया कि आज भी हर चार में से एक लड़की पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती। यानी पीरियड्स अब सिर्फ शारीरिक दर्द या असुविधा का मुद्दा नहीं रहे, बल्कि यह शिक्षा का 'कटऑफ पॉइंट' बन चुके हैं।

पढ़ाई से शादी तक की दूरी

टाटा ट्रस्ट की 2025 की रिपोर्ट इस समस्या को एक और खतरनाक मोड़ पर ले जाती है। रिपोर्ट कहती है कि कई परिवारों में लड़की के पीरियड्स शुरू होने के बाद उसकी पढ़ाई से ज्यादा उसके ब्याह की चिंता होने लगती है। कारण बेहद साधारण और चौंकाने वाले हैं—सैनिटरी पैड महंगे हैं, स्कूल में शौचालय नहीं हैं, पैड फेंकने की व्यवस्था नहीं है और समाज में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं है।यानी पीरियड्स एक जैविक प्रक्रिया से निकलकर सामाजिक निर्णयों का आधार बन जाते हैं। लड़की का शरीर जैसे ही परिपक्व होता है, समाज उसकी शिक्षा को गैरजरूरी और शादी को जरूरी मानने लगता है।

शर्म का बोझ और चुप्पी की साजिश

पीरियड्स को लेकर समाज में बनी चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। घरों में इसे फुसफुसाकर बताया जाता है। स्कूलों में या तो पढ़ाया ही नहीं जाता या औपचारिकता निभा दी जाती है। गांवों में आज भी कई जगह लड़कियों को रसोई में जाने, पूजा करने या बाहर निकलने से रोका जाता है। यही शर्म धीरे-धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है और लड़की खुद को अलग-थलग महसूस करने लगती है।

सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक दखल

इसी चुप्पी और भेदभाव को चुनौती देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है। यानी जैसे जीने का अधिकार, वैसे ही सम्मान के साथ पीरियड्स मैनेज करने का भी अधिकार।कोर्ट का

आदेश साफ है। देश का हर स्कूल चाहे सरकारी हो या निजी, शहर में हो या गांव में उसे छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही साफ-सुथरे टॉयलेट, पानी और सुरक्षित डिस्पोजल सिस्टम की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन की होगी।यह फैसला सिर्फ सुविधा देने का नहीं, बल्कि सोच बदलने का है। पहली बार पीरियड्स को किसी योजना या दया की नजर से नहीं, बल्कि अधिकार के तौर पर देखा गया है। अब यह मुद्दा सिर्फ सरकारी घोषणाओं या कागजी नीतियों तक सीमित नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह साफ हो चुका है कि पीरियड्स कोई एहसान नहीं हैं। यह अधिकार है। सवाल अब पैड मिलने या न मिलने का नहीं, बल्कि इस अधिकार के ईमानदार क्रियान्वयन का है।

हम कब बोलेंगे

आज सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि आंकड़े क्या कहते हैं या अदालत ने क्या कहा। असली सवाल यह है कि समाज कब खुले तौर पर इस मुद्दे पर बात करेगा। कब मां-बाप अपनी बेटियों से बिना झिझक बात करेंगे। कब स्कूलों में पीरियड्स को पाठ्यक्रम का स्वाभाविक हिस्सा बनाया जाएगा। कब लड़कियों को यह महसूस होगा कि उनके शरीर में होने वाला बदलाव शर्म की नहीं, समझ की जरूरत है।पीरियड्स पर चुप्पी अब सिर्फ सामाजिक कमजोरी नहीं, बल्कि एक अन्याय बन चुकी है। यह चुप्पी शिक्षा छीन रही है, सपने तोड़ रही है और भविष्य को सीमित कर रही है।

एपस्टीन फ़ाइल्स विवाद

पीएम मोदी के नाम पर सियासी संग्राम, विदेश मंत्रालय का सख्त खंडन

@ रिंकू विश्वकर्मा

अमेरिकी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जुड़ी हज़ारों गोपनीय फ़ाइलों के सार्वजनिक होने के बाद भारत की राजनीति में एक नया और तीखा विवाद खड़ा हो गया है। इन फ़ाइलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम होने के कांग्रेस के दावे ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है और इसे एक "दोषी अपराधी की बेकार की बकवास" करार दिया है। यह पूरा मामला न केवल अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ों, बल्कि देश की राजनीतिक प्रतिष्ठा, कूटनीतिक छवि और सत्ता-विपक्ष के टकराव से भी जुड़ गया है। सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं और साथ ही सरकार की ओर से सख़्त जवाब भी दिया जा रहा है।

क्या हैं एपस्टीन फ़ाइल्स?

अमेरिका के न्याय विभाग ने यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफ़री एपस्टीन से जुड़े लाखों दस्तावेज़ सार्वजनिक किए हैं। इनमें लगभग 30 लाख पन्ने, 1.8 लाख तस्वीरें और करीब 2,000 वीडियो शामिल हैं। ये फ़ाइलें एपस्टीन के जेल में रहने के दौरान तैयार किए गए दस्तावेज़ों, मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट, उसकी मौत से जुड़ी जानकारियों और कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों के साथ हुए ईमेल संवादों को उजागर करती हैं।इन दस्तावेज़ों को सार्वजनिक करने की एक समय-सीमा तय की गई थी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में कानून का रूप दिया गया था। हालांकि तय समय-सीमा से करीब छह हफ्ते बाद इतनी बड़ी संख्या में फ़ाइलें सार्वजनिक की गईं।

कांग्रेस का दावा और आरोप

इन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर कांग्रेस ने दावा किया कि 'एपस्टीन फ़ाइल्स' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आकर हमारे तीन सवालों का जवाब दें।कांग्रेस का दावा एक ईमेल संदेश पर आधारित है, जो कथित तौर पर 9 जुलाई 2017 को जेफ़री एपस्टीन ने लिखा था। कांग्रेस के अनुसार, इस ईमेल में एपस्टीन ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उससे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इसराइल में नाच-गाकर कूटनीतिक संदेश दिया। कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री मोदी और एपस्टीन के बीच कथित संबंधों से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए।कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 25-26 जून 2017 को अमेरिका में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे और इसके बाद 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इसराइल की यात्रा पर गए। इसके तीन दिन बाद एपस्टीन द्वारा लिखा गया ईमेल इस पूरी कड़ी को जोड़ता है। कांग्रेस ने तीन सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री मोदी एपस्टीन से किस तरह की सलाह ले रहे थे? अमेरिकी राष्ट्रपति के किस फायदे के लिए इसराइल में यह कूटनीतिक गतिविधि की गई? एपस्टीन के इट वर्क्ड कहने का असली मतलब क्या है?कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय गरिमा और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा मुद्दा बताते हुए प्रधानमंत्री से सीधे जवाब की मांग की।

क्या यहीं खत्म होगी कहानी?

अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि यह एक व्यापक दस्तावेज़ पहचान और समीक्षा प्रक्रिया का अंत है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच के मुताबिक, विभाग के स्तर पर अब इस मामले में काम लगभग पूरा हो चुका है।हालांकि डेमोक्रेट्स का आरोप है कि करीब 25 लाख दस्तावेज़ बिना किसी ठोस वजह के अभी भी रोके गए हैं। ऐसे में यह बहस अभी खत्म नहीं हुई है कि एपस्टीन से जुड़े सभी सच सामने आए हैं या नहीं।

विदेश मंत्रालय का सख़्त जवाब

इन आरोपों पर भारत सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसराइल यात्रा पूरी तरह आधिकारिक थी और इससे इतर ईमेल में कही गई बातें एक दोषी अपराधी की मनगढ़ंत और निरर्थक बातें हैं।विदेश मंत्रालय ने कहा, "हमें तथाकथित एपस्टीन फ़ाइल्स से जुड़े एक ईमेल की रिपोर्ट मिली है। इसमें प्रधानमंत्री और उनकी इसराइल यात्रा का उल्लेख है। लेकिन जुलाई 2017 की आधिकारिक यात्रा के अलावा बाकी बातें एक दोषी अपराधी की बेकार की बकवास से ज्यादा कुछ नहीं हैं, जिन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज़ किया जाना चाहिए।"सरकार ने इसे राजनीति से प्रेरित आरोप बताते हुए कहा कि ऐसे दस्तावेज़ों को संदर्भ से काटकर पेश करना न केवल भ्रामक है, बल्कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी है।

अंतरराष्ट्रीय संदर्भ और हाई-प्रोफाइल नाम

इन फ़ाइलों में केवल भारत ही नहीं, बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र इन दस्तावेज़ों में सैकड़ों बार किया गया है। ट्रंप और एपस्टीन की दोस्ती जगज़ाहिर रही है, हालांकि ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों के संबंध वर्षों पहले खत्म हो गए थे और उन्हें एपस्टीन के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी।इसके अलावा टेक अरबपति एलन मस्क और एपस्टीन के बीच हुए ईमेल संवाद भी सामने आए हैं। हालांकि मस्क पर किसी भी तरह के गलत काम का आरोप नहीं लगा है। मस्क पहले ही कह चुके हैं कि एपस्टीन ने उन्हें अपने निजी द्वीप पर आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था।

भारत में सियासी असर

भारत में यह मुद्दा फिलहाल सियासी आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित है। विपक्ष इसे सरकार की जवाबदेही से जोड़कर देख रहा है, जबकि सरकार इसे एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी के बयानों के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश बता रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक किसी आधिकारिक जांच या प्रमाणिक दस्तावेज़ से इन आरोपों की पुष्टि नहीं होती, तब तक यह मामला राजनीतिक बयानबाज़ी से आगे बढ़ना मुश्किल है। विदेश मंत्रालय के खंडन के बाद सरकार का रुख साफ है कि वह ऐसे आरोपों को गंभीरता से लेने के पक्ष में नहीं है।एपस्टीन फ़ाइल्स ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज़ किस तरह घरेलू राजनीति में तूफान खड़ा कर सकते हैं। एक ओर कांग्रेस इसे राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार इसे सिरे से खारिज कर रही है।

सच्चाई क्या है, यह तय करने के लिए ठोस सबूत और तथ्य ही आधार बन सकते हैं, न कि दोषी अपराधियों के कथित ईमेल।फिलहाल, यह विवाद भारतीय राजनीति में एक और तीखे टकराव के रूप में दर्ज हो गया है, जहां सवाल भी हैं, जवाब भी और आरोपों की आग भी।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

मैं पिता के बारे में नहीं सोचता

जब भी माँ के बारे में सोचता हूँ,
माँ नहीं, उसके चेहरे की झुर्रियों और

दांतों की बेतरतीबी के बारे में सोचता हूँ
माँ के चेहरे की झुर्रियाँ केवल झुर्रियाँ नहीं हैं

उसमें इतिहास छिपा है मेरे पूर्वजों का
वह झुर्रियाँ उतरती हुई उम्र की सलवटें नहीं हैं

किसी पुराने दस्तावेज़ का अक्षर हैं
जैसे कि इतिहास की मोहरें

फिर से पढ़े जाने की मांग कर रही हों।
माँ के दाँतों की बेतरतीबी

दाँतों की बेतरतीबी नहीं है
उसके जीवन की बेतरतीबी है

माँ जब याद आती हैं
सिर्फ़ स्मृतियाँ नहीं खुलतीं—

सत्ता की खिड़कियाँ खुल जाती हैं,
और मैं देख पाता हूँ

कि कितनी पीढ़ियों का आराम
कितनी पीढ़ियों की चुप्पी पर टिका है।

मैं पिता के बारे में नहीं सोचता,
अज्ञेय ने लिखा है कि पिताओं के बारे में नहीं सोचते,

पिताओं के बारे में सोचने से
अपनी कलई खुल जाती है

अज्ञेय यह लिखना भूल गए.
कि माँओं के बारे में नहीं सोचा करते

माँओं के बारे में सोचने से
पिताओं की कलई खुल जाती है।

अजय कुमार यादव
नई पीढ़ी के कवि।

मन:स्थिति

जब जीवन है निरर्थक
सब रास्ते हैं अंधकारमय

फिर क्यों बैठा हूँ
इन मुर्दा दीवारों के बीच—जीवित

क्यों न कर ही लूँ
इसी कमरे में—जीवन का अंत

लेकिन यह क्या
कि पलटता जा रहा हूँ पृष्ठ

शायद मैं जानता हूँ
कोई एक कविता बचा लेगी मुझे।

अजय नेगी
(नई पीढ़ी के कवि-लेखक)

बारामती हादसा: 3 किमी दृश्यता में भी क्यों गिरी मौत की छाया अजित पवार की दुर्घटना और नेताओं के दुखद इतिहास

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में हुआ, जो पूरे देश को झकझोर गया। अजित पवार, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, मुंबई से बारामती जा रहे थे। उनका विमान लियरजेट 45XR था, जिसका रजिस्ट्रेशन VT-SSK था। इस विमान में पवार के अलावा दो पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर सवार थे। सुबह करीब 8 बजे विमान ने मुंबई से उड़ान भरी और बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश की। लेकिन पहली बार लैंडिंग नहीं हो सकी, इसलिए पायलट ने गो-अराउंड किया, यानी दोबारा घूमकर कोशिश की। दूसरी कोशिश में विमान रनवे से सिर्फ 200 मीटर दूर एक खुले मैदान में गिर गया और आग लग गई। सभी पांच लोग मौके पर ही मारे गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि बचाव करना मुश्किल हो गया। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि जांच शुरू हो गई है और ब्लैक बॉक्स की मदद से सच्चाई पता चलेगी। बारामती एयरपोर्ट एक छोटा हवाई अड्डा है, जहां कोई बड़ा एटीसी नहीं है, सिर्फ एयरफील्ड स्टाफ मौसम की जानकारी देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार, उस समय हवा शांत थी और दृश्यता 3000 मीटर थी। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि इतनी दृश्यता में भी लैंडिंग जोखिम भरी हो सकती है, खासकर अगर सूरज की रोशनी आंखों में पड़ रही हो। इस हादसे ने राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के मजबूत स्तंभ थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए कहा कि उनका जाना बड़ा नुकसान है। विरोधी दल कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की, क्योंकि कुछ लोग कम दृश्यता को वजह मान रहे हैं, जबकि कुछ सीसीटीवी फुटेज से कहते हैं कि दृश्यता ठीक थी। हादसे के बाद बारामती में शोक की लहर दौड़ गई, जहां पवार का परिवार और समर्थक सदमे में हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हवाई यात्रा में कितनी सावधानी जरूरी है, चाहे नेता हों या आम आदमी। जांच रिपोर्ट आने तक अटकलें लगती रहेंगी, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। कुल मिलाकर, यह हादसा एक बड़ी त्रासदी है जो राजनीतिक और सुरक्षा के सवाल उठाता है।

हादसे की शुरुआत: मुंबई से बारामती तक का सफर कैसे बना आखिरी

दृश्यता की गुत्थी: 3 किमी में क्यों छिप गया रनवे

हादसे की सबसे बड़ी पहेली है कि 3 किमी की दृश्यता होने पर भी पायलट को रनवे क्यों नहीं दिखा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, एयरफील्ड स्टाफ ने पायलट को बताया कि दृश्यता 3000 मीटर है और हवा शांत है। सामान्य नियमों में विजुअल फ्लाइट रूल्स के लिए 5 किमी दृश्यता जरूरी होती है, लेकिन स्पेशल वीएफआर में 3 किमी की इजाजत मिल सकती है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि 3 किमी दृश्यता में भी अगर सूरज की किरणें सीधे आंखों में पड़ रही हों, तो 2 किमी दूर की चीज भी नहीं दिख सकती। बारामती एयरपोर्ट एक टेबलटॉप रनवे है, यानी ऊंचाई पर बना हुआ, जहां ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है। पायलट को लग सकता है कि रनवे करीब है, लेकिन असल में दूर हो। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि विमान तेज गति से आ रहा था और आखिरी पलों में बाईं तरफ मुड़ गया, शायद सुधार करने की कोशिश में। कुछ लोग कहते हैं कि कम दृश्यता के कारण पायलट ने गलत अनुमान लगाया। लेकिन विरोधी दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उस सुबह बारामती में दृश्यता साफ थी, वे खुद वहां थे और 3 किमी तक सब दिख रहा था। आईएमडी की सेवाएं बारामती में नहीं हैं, इसलिए मौसम की जानकारी सही नहीं हो सकती। जांच में ब्लैक बॉक्स से उड़ान डेटा और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो बताएगी कि पायलट क्या बात कर रहे थे। कप्तान सुमीत सभरवाल के पास 8200 घंटे का अनुभव था, फिर भी हादसा हो गया। कुछ सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें फैलीं कि को-पायलट महिला होने से गलती हुई, लेकिन यह झूठ है क्योंकि मुख्य पायलट पुरुष थे। कुल मिलाकर, दृश्यता एक बड़ा फैक्टर लगता है, लेकिन तकनीकी खराबी या मानवीय भूल भी हो सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि छोटे एयरपोर्ट पर बेहतर मौसम सेवाएं क्यों नहीं हैं। जांच से साफ होगा कि 3 किमी दृश्यता पर्याप्त थी या नहीं, और भविष्य में ऐसी गलतियां कैसे रोकी जाएं। यह घटना सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाती है और हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और तकनीक के बीच संतुलन जरूरी है।

संभावित कारण: मानवीय गलती, मौसम या मशीन की खराबी

अजित पवार के विमान हादसे की जांच में कई संभावित कारण सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से लगता है कि पायलट की गलत जजमेंट एक वजह हो सकती है, खासकर कम दृश्यता में लैंडिंग की कोशिश करते हुए। विमान ने दो बार लैंडिंग ट्राई की, पहली बार गो-अराउंड हुआ क्योंकि रनवे नहीं दिखा। दूसरी बार लैंडिंग क्लियरेंस मिली, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया और विमान क्रैश हो गया। विशेषज्ञ कहते हैं कि तेज गति, आखिरी मिनट में सुधार या तकनीकी असंतुलन ने रोल कराया। बारामती का रनवे ऊंचाई पर है, जहां गलत अनुमान लगना आसान है। कुछ रिपोर्ट्स में कम दृश्यता को मुख्य वजह बताया गया, लेकिन स्थानीय गवाह कहते हैं कि सुबह कोहरा नहीं था। ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालकर पता चलेगा कि इंजन में कोई खराबी थी या नहीं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जांच कर रहा है। कुछ लोग साजिश की बात कर रहे हैं, क्योंकि पवार ने हाल में भ्रष्टाचार की फाइलों का जिक्र किया था, लेकिन यह सिर्फ अटकलें हैं। पायलटों का अनुभव अच्छा था, फिर भी हादसा हुआ, जो बताता है कि कई फैक्टर एक साथ आ सकते हैं। छोटे चार्टर्ड विमानों में मौसम ब्रिफिंग आईएमडी से नहीं मिलती, जो एक कमी है। सीसीटीवी से पता चलता है कि विमान दूर से दिख रहा था, तो दृश्यता इतनी खराब कैसे? जांच से साफ होगा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि नेताओं की सुरक्षा में और सुधार की जरूरत है। कुल मिलाकर, हादसा एक चेतावनी है कि हवाई यात्रा में छोटी-छोटी बातें बड़ी त्रासदी ला सकती हैं। जांच पूरी होने पर सच्चाई सामने आएगी और भविष्य के लिए सबक मिलेगा।

इतिहास की दुखद घटनाएं: पहले भी नेताओं ने ऐसे गंवाई जान

अजित पवार का हादसा नया नहीं है, भारत में कई बड़े नेता हवाई दुर्घटनाओं में जान गंवा चुके हैं। 1980 में संजय गांधी, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, दिल्ली में एक छोटे विमान में स्टंट करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वे कांग्रेस के बड़े नेता थे और उनकी मौत ने राजनीति को हिला दिया। 2001 में माधवराव सिंधिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक चार्टर्ड विमान दुर्घटना में मारे गए। वे रैली जा रहे थे। 2002 में लोकसभा स्पीकर जीएमसी बालयोगी आंध्र प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में गए। 2005 में ओपी जिंदल हरियाणा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए। 2009 में वाईएस राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, नल्लमाला जंगल में हेलीकॉप्टर गिरने से मारे गए। 2011 में दोरजी खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गए। 2021 में जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तमिलनाडु में एमआई-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए। 2025 में विजय रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, एक बड़े विमान हादसे में मारे गए, जिसमें 240 से ज्यादा लोग गए। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि हवाई यात्रा में जोखिम कितना है, खासकर नेताओं के लिए जो अक्सर छोटे विमानों या हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। ज्यादातर मामलों में कम दृश्यता, मौसम खराबी या तकनीकी खराबी वजह बनी। इन हादसों ने जांच और सुरक्षा नियमों में सुधार लाया, लेकिन फिर भी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अजित पवार का जाना इस सूची में नया नाम जोड़ता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नेताओं की सुरक्षा पर्याप्त है। यह इतिहास हमें चेतावनी देता है कि सावधानी बरतनी जरूरी है।

सबक और भविष्य: सुरक्षा में सुधार की जरूरत

ये हादसे हमें कई सबक देते हैं कि हवाई सुरक्षा में और सुधार जरूरी है। अजित पवार की दुर्घटना से साफ है कि छोटे एयरपोर्ट पर बेहतर मौसम सेवाएं और एटीसी सिस्टम लगाने चाहिए। आईएमडी की सेवाएं हर जगह उपलब्ध हों। चार्टर्ड विमानों के लिए सख्त चेकिंग और पायलट ट्रेनिंग पर जोर दें। इतिहास की घटनाओं से पता चलता है कि ज्यादातर हादसे कम दृश्यता या मौसम से होते हैं, इसलिए मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाएं। नेताओं की यात्रा में वैकल्पिक प्लान रखें, जैसे ट्रेन या सड़क। जांच एजेंसियां जल्दी रिपोर्ट दें ताकि सुधार हो सके। समाज को भी जागरूक होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर गलत अफवाहें न फैलाएं, जैसे पायलट की जेंडर पर टिप्पणी। यह घटना राजनीति पर असर डालेगी, महाराष्ट्र में नई समीकरण बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या हम इन हादसों से सीखेंगे। सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाएं। कुल मिलाकर, यह त्रासदी एक चेतावनी है कि जीवन अनमोल है, और सावधानी से ही बचाव संभव है।

राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं हम
भारत श्री

चांदी की कीमतों में भारी गिरावट: तीन दिनों में 1.50 लाख रुपये सस्ती, सोने पर भी असर

चांदी की कीमतें हाल ही में आसमान छू रही थीं, लेकिन अचानक तीन दिनों में सब कुछ बदल गया। 29 जनवरी 2026 को चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 4.20 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन 1 फरवरी तक यह गिरकर 2.65 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास आ गई। यानी कुल मिलाकर 1.55 लाख रुपये की गिरावट आई, जो लगभग 1.50 लाख के करीब है। यह गिरावट इतनी तेज थी कि बाजार में हड़कंप मच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट थी, जहां 30 जनवरी को ही चांदी 37 प्रतिशत तक गिर गई। वैश्विक बाजार में भी स्पॉट सिल्वर 121.64 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 84.63 डॉलर तक पहुंच गया। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह निवेशकों का मुनाफा वसूलना था, क्योंकि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थीं। अमेरिकी डॉलर की मजबूती ने भी दबाव डाला, क्योंकि डॉलर मजबूत होने से सोना-चांदी जैसे डॉलर में कारोबार होने वाले सामान महंगे हो जाते हैं और मांग घट जाती है। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेड चेयर के लिए केविन वार्श को नामित किया, जो एक कड़े रुख वाले व्यक्ति हैं, जिससे ब्याज दरों पर असर पड़ा और बाजार में बिकवाली बढ़ गई। भारत में एमसीएक्स पर सिल्वर फ्यूचर्स में भी निचला सर्किट लग गया, यानी ट्रेडिंग रुक गई। सोने की बात करें तो उसकी कीमत भी 1.83 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से गिरकर 1.38 लाख रुपये तक पहुंच गई, लेकिन चांदी जितनी तेज गिरावट नहीं आई। बजट 2026 के दिन बाजार खुला रहा, लेकिन कीमतें और गिरती रहीं। यह स्थिति निवेशकों के लिए सोचने वाली है, क्योंकि पिछले दो सालों में चांदी की कीमतें 326 प्रतिशत बढ़ी थीं, लेकिन अब सुधार आ रहा है। बाजार विशेषज्ञ कहते हैं कि यह अस्थायी है, लेकिन लंबे समय में चांदी की मांग मजबूत रहेगी क्योंकि उद्योगों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। कुल मिलाकर, यह गिरावट बाजार की अस्थिरता को दिखाती है, जहां तेज बढ़ोतरी के बाद सुधार आना स्वाभाविक है।

गिरावट की शुरुआत: बाजार में क्या हुआ?

गिरावट के मुख्य कारण: क्यों आई इतनी तेजी से कमी?

चांदी की कीमतों में यह गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि कई कारणों से हुई। सबसे बड़ा कारण निवेशकों का मुनाफा वसूलना था। पिछले महीने चांदी की कीमतें 42 प्रतिशत बढ़ी थीं, जिससे निवेशक ऊंचे दाम पर बेचने लगे। जब कीमतें बहुत तेज बढ़ती हैं, तो लोग बेचकर पैसा निकाल लेते हैं, जिससे कीमतें गिरती हैं। दूसरा कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। डॉलर मजबूत होने से सोना-चांदी की मांग घट जाती है, क्योंकि ये डॉलर में खरीदे जाते हैं और विदेशी खरीदारों के लिए महंगे हो जाते हैं। 30 जनवरी को डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, क्योंकि ट्रंप ने फेड चेयर के लिए केविन वार्श को चुना, जो ब्याज दरों को ऊंचा रखने के पक्ष में हैं। इससे बाजार में डर फैला और बिकवाली बढ़ गई। तीसरा कारण मार्जिन बढ़ना था। सीएमई ग्रुप ने सिल्वर फ्यूचर्स पर मार्जिन बढ़ा दिया, जिससे ट्रेडर्स को ज्यादा पैसा लगाना पड़ा और उन्होंने अपनी पोजीशन बेच दी। भारत में भी एमसीएक्स पर यह असर पड़ा, जहां सिल्वर 27 प्रतिशत गिरकर 2.91 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर भी सिल्वर 37 प्रतिशत गिरा, जो रिकॉर्ड है। इसके अलावा, बजट 2026 से पहले अनिश्चितता थी, क्योंकि आयात शुल्क में कटौती की अफवाहें थीं, जिससे कीमतें और दब गईं। सोने की कीमतें भी इसी वजह से गिरीं, लेकिन चांदी ज्यादा प्रभावित हुई क्योंकि उसकी कीमतें ज्यादा बढ़ी थीं। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सुधार जरूरी था, क्योंकि बाजार ओवरबॉट था, यानी खरीदारी ज्यादा हो गई थी। लंबे समय में चांदी की मांग मजबूत रहेगी, क्योंकि सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल, यह गिरावट निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह देती है। कुल मिलाकर, ये कारण बाजार की गतिशीलता को समझाते हैं, जहां तेज बढ़ोतरी के बाद गिरावट आना सामान्य है, लेकिन इतनी तेज गिरावट दुर्लभ है।

सोने का हाल: गिरावट लेकिन कम असर

सोने की कीमतें भी चांदी की तरह गिरीं, लेकिन उतनी तेज नहीं। 29 जनवरी को सोना 1.83 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन 1 फरवरी तक यह 1.38 लाख रुपये तक पहुंच गया, यानी लगभग 45,000 रुपये की गिरावट। प्रतिशत में देखें तो सोना 9 प्रतिशत गिरा, जबकि चांदी 37 प्रतिशत। कारण वही हैं: मुनाफा वसूलना, डॉलर की मजबूती और फेड चेयर की नामांकन। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स में भी निचला सर्किट लगा, और कीमतें 1.36 लाख तक गिरीं। वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड 5,376 डॉलर से गिरकर 4,887 डॉलर प्रति औंस हो गया। भारत में सर्राफा बाजार में सोना 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन बजट के दिन और गिरावट आई। बजट 2026 में आयात शुल्क में कटौती की उम्मीद थी, जो सोने की कीमतों को और प्रभावित कर सकती है। पिछले महीने सोना 20 प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन अब सुधार आ रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सोना सुरक्षित निवेश है, और यह गिरावट खरीदने का मौका हो सकता है। लंबे समय में सोने की मांग मजबूत रहेगी, क्योंकि मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनाव हैं। लेकिन फिलहाल, बाजार अस्थिर है। ईटीएफ में भी सोने की कीमतें 16 प्रतिशत गिरीं। निवेशकों को सलाह है कि घबराएं नहीं, क्योंकि पिछले दो सालों में सोना 150 प्रतिशत बढ़ा है। यह गिरावट बाजार को संतुलित कर रही है। कुल मिलाकर, सोने का हाल चांदी से बेहतर है, लेकिन दोनों पर वैश्विक कारकों का असर है।

बाजार पर असर और भविष्य की संभावनाएं: क्या होगा आगे?

इस गिरावट का बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। एमसीएक्स पर ट्रेडिंग रुक गई, और ईटीएफ में 24 प्रतिशत तक गिरावट आई। हिंदुस्तान जिंक और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों के शेयर गिरे। कुल मिलाकर, सोने-चांदी की मार्केट कैप में 5 ट्रिलियन डॉलर की कमी आई। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह अस्थायी है। चांदी की मांग उद्योगों से मजबूत है, जैसे सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। सोने के लिए भी सुरक्षित निवेश का दर्जा बरकरार है। बजट 2026 में अगर आयात शुल्क कम होता है, तो कीमतें और गिर सकती हैं, लेकिन लंबे समय में फायदा होगा। निवेशकों को सलाह है कि गिरावट में खरीदें, लेकिन सावधानी से। बाजार में अस्थिरता है, इसलिए छोटे निवेश करें। पिछले महीने चांदी 30 प्रतिशत बढ़ी थी, इसलिए सुधार जरूरी था। वैश्विक स्तर पर सिल्वर की आपूर्ति कम है, जो कीमतों को सपोर्ट करेगी। भारत में त्योहारों का मौसम आने वाला है, जिससे मांग बढ़ेगी। कुल मिलाकर, यह गिरावट सोचने का मौका देती है कि बाजार हमेशा ऊपर नहीं जाता, लेकिन मजबूत बुनियाद वाले एसेट लंबे समय में फायदा देते हैं।

संतुलित नजरिया: निवेशकों के लिए क्या सबक?

यह गिरावट हमें सिखाती है कि बाजार में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। चांदी और सोने जैसी चीजें सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन तेज बढ़ोतरी के बाद गिरावट भी आ सकती है। निवेशक घबराएं नहीं, बल्कि लंबे समय का सोचें। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है, तो गिरावट में खरीदें, क्योंकि कीमतें फिर बढ़ेंगी। लेकिन जोखिम लें जितना सहन कर सकें। बाजार में कई दृष्टिकोण हैं: कुछ कहते हैं कि यह खरीदने का समय है, जबकि कुछ इंतजार करने की सलाह देते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, जैसे मुद्रास्फीति और युद्ध के डर, जो सोना-चांदी को सपोर्ट करते हैं। भारत में भी अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन डॉलर का असर पड़ता है। कुल मिलाकर, यह घटना बाजार की जटिलता को दिखाती है, जहां कई कारक मिलकर असर डालते हैं।

भारत-ईयू व्यापार समझौता: अमेरिका की चिढ़ और भारत के फायदे

समझौते की पृष्ठभूमि और मुख्य बातें

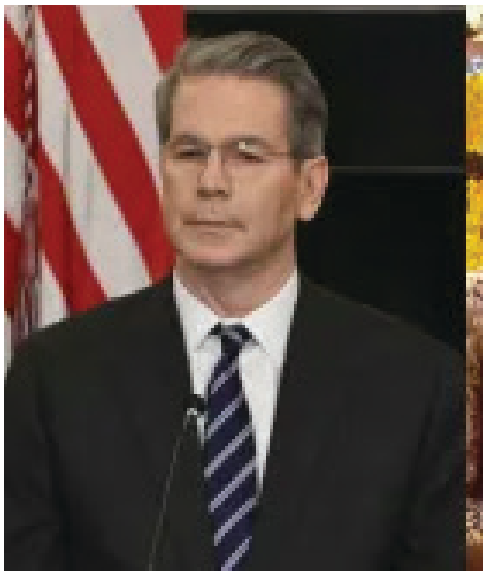

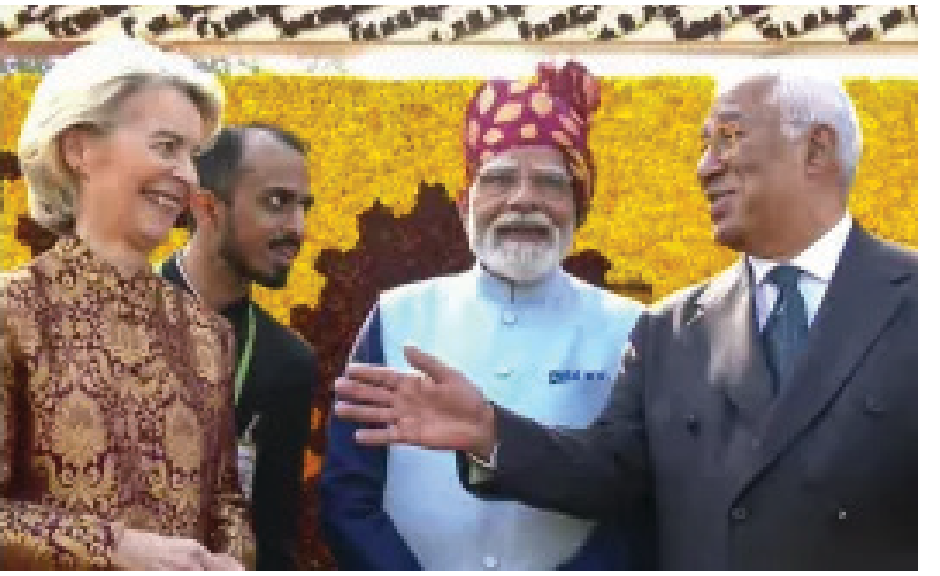

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच 27 जनवरी 2026 को एक बड़ा व्यापार समझौता हुआ है, जिसे 'मदर ऑफ ऑल डील्स' कहा जा रहा है। यह समझौता लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद पूरा हुआ और अगले साल से लागू होगा। इसमें दोनों पक्षों के बीच 90 प्रतिशत से ज्यादा माल पर टैरिफ हटा दिए जाएंगे या कम कर दिए जाएंगे। भारत से ईयू को निर्यात होने वाले सामान जैसे कपड़े, चमड़े के उत्पाद, दवाएं, रसायन और गहने पर ड्यूटी बहुत कम हो जाएगी। वहीं, ईयू से भारत आने वाली कारों पर टैरिफ 110 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे वोक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी। सेवाओं के क्षेत्र में भी बाधाएं कम होंगी, जैसे टेलीकॉम और अकाउंटिंग। हालांकि, कृषि और डेयरी उत्पादों को समझौते से बाहर रखा गया है ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापार साथी है, और 2025 में भारत ने ईयू को 6.8 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया जबकि आयात 5.5 लाख करोड़ का रहा। यह समझौता दोनों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है, जो 12.5 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के बीच यह डील भारत को वैकल्पिक बाजार देती है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि इससे भारत को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन यह अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। क्या यह समझौता वैश्विक व्यापार की दिशा बदल देगा? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि यह दिखाता है कि देश अपनी जरूरतों के हिसाब से साझेदारियां चुन रहे हैं। समझौते से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन ईयू को भी चीन पर निर्भरता कम करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर, यह डील वैश्विक अनिश्चितताओं में स्थिरता लाने की कोशिश है।

अमेरिका की नाराजगी के कारण

अमेरिका इस भारत-ईयू समझौते से बहुत चिढ़ा हुआ है, क्योंकि उसके अधिकारी इसे यूरोप की गलती मानते हैं। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईयू रूस-यूक्रेन युद्ध के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन भारत से व्यापार करके अप्रत्यक्ष रूप से उस युद्ध को फंडिंग दे रहा है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और ईयू को बेचता है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, लेकिन ईयू ने फिर भी यह डील साइन की। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमिसन ग्रीर ने इसे निराशाजनक बताया और कहा कि इससे भारत को ईयू बाजार में ज्यादा मौके मिलेंगे। ट्रंप प्रशासन मानता है कि ईयू व्यापार को जियोपॉलिटिकल मुद्दों से ऊपर रख रहा है, जो अमेरिका की रणनीति के खिलाफ है। ट्रंप ने ईयू को रक्षा खर्च और अन्य मुद्दों पर आलोचना की है, और भारत पर भी दबाव बनाया है। यह डील ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के लिए झटका है, क्योंकि यह दिखाती है कि ईयू और भारत अमेरिकी दबाव से बचने के लिए आपस में जुड़ रहे हैं। क्या अमेरिका की यह चिढ़ वैश्विक व्यापार में उसके प्रभाव को कम कर देगी? यह विचारणीय है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीतियां कई देशों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पर मजबूर कर रही हैं। ईयू ने अमेरिका के साथ अपनी व्यापार बातचीत रोक दी है, और कई यूरोपीय देश ट्रंप की वेस्ट एशिया नीतियों से दूर रह रहे हैं। भारत ने भी ट्रंप की आलोचना का जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप अपनी डील पूरी की। कुल मिलाकर, यह अमेरिका के लिए एक संकेत है कि दुनिया उसके इशारों पर नहीं चलेगी। हालांकि, अमेरिका का कहना है कि यह डील यूक्रेन के हितों के खिलाफ है, लेकिन ईयू का मानना है कि व्यापार और राजनीति अलग-अलग हैं।

भारत को होने वाले फायदे

इस समझौते से भारत को कई बड़े फायदे हैं, जैसा कि अमेरिकी अधिकारियों ने भी माना है। भारत के 99.5 प्रतिशत सामान पर ईयू में टैरिफ 3.8 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि ईयू के 96.6 प्रतिशत सामान पर भारत टैरिफ हटाएगा। कपड़े और चमड़े के उत्पादों पर 10 प्रतिशत ड्यूटी तुरंत खत्म हो जाएगी, जिससे आगरा, कानपुर और कोल्हापुर जैसे इलाकों की इंडस्ट्री को फायदा होगा। ईयू का 100 बिलियन डॉलर का बाजार भारतीय निर्यातकों के लिए खुल जाएगा। दवाओं और रसायनों पर 97.5 प्रतिशत टैरिफ मुक्त होंगे, और जेनेरिक दवाओं की मंजूरी आसान होगी, जिससे व्यापार 20-30 प्रतिशत सालाना बढ़ सकता है। रक्षा क्षेत्र में ईयू की फैक्टरियां भारत में लग सकती हैं, और ईयू के सेफ फंड्स तक पहुंच मिलेगी। 2024 में भारत का रक्षा उत्पादन 150,000 करोड़ रुपये था, और निर्यात 25,000 करोड़, जो अब बढ़ सकता है। गहनों पर जीरो ड्यूटी से भी फायदा होगा। कुल 90.7 प्रतिशत निर्यात तुरंत ड्यूटी-फ्री होंगे। क्या यह फायदे भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत बनाएंगे? यह सोचने लायक है, क्योंकि यह डील अमेरिकी टैरिफ के नुकसान की भरपाई कर सकती है। भारत का ईयू के साथ व्यापार अधिशेष है, जो और बढ़ेगा। हालांकि, ईयू को भी फायदे हैं, जैसे वाइन और शराब पर टैरिफ 150 प्रतिशत से 20 प्रतिशत होना, कारों पर 110 से 10 प्रतिशत, और मशीनरी, रसायन, दवाओं पर ड्यूटी खत्म। भारत ईयू को चीन का विकल्प बन सकता है, जिससे सप्लाई चेन मजबूत होंगी। भारत ने किसानों की सुरक्षा के लिए कृषि बाहर रखी, जो समझदारी है। कुल मिलाकर, यह डील भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगी और नौकरियां बढ़ाएगी।

ट्रंप के टैरिफ पर असर

ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं (पहले 10 प्रतिशत से कम थे), जिसमें 25 प्रतिशत रूसी तेल खरीदने पर और 25 प्रतिशत अन्य कारणों से। इससे भारतीय निर्यात प्रभावित हुए हैं- कुछ महीनों में 28.5 प्रतिशत गिरावट, और नवंबर 2025 में कुल निर्यात 11 प्रतिशत कम। 2024-25 में 86.5 बिलियन डॉलर का निर्यात 2025-26 में 50 बिलियन तक गिर सकता है। लेकिन भारत-ईयू डील से वैकल्पिक बाजार मिलेगा, जहां भारतीय सामान सस्ते होंगे, जैसे चीनी सामान। डायमंड और गहनों जैसे सेक्टरों में नुकसान की भरपाई हो सकती है। ओआरएफ के मीहिर शर्मा कहते हैं कि यह डील भारत के विकल्पों का संकेत है, जो ट्रंप के टैरिफ को कम असरदार बनाती है। ईयू ने भारतीय सीफूड प्रोसेसिंग को मंजूरी दी, जो निर्यात बढ़ाएगी। क्या ट्रंप के टैरिफ अब बेअसर हो जाएंगे? यह विचार करने योग्य है, क्योंकि वैश्विक व्यापार में देश दबाव से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। ट्रंप ने कनाडा पर 100 प्रतिशत टैरिफ की धमकी दी, जिससे कनाडा-चीन डील रुक गई, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने 28-29 जनवरी 2026 को चीन का दौरा किया, जो अमेरिकी प्रभाव कम होने का संकेत है। अमेरिका मानता है कि उसका ईयू के साथ व्यापार 150 लाख करोड़ है, जो खतरे में पड़ सकता है। हालांकि, ट्रंप की नीति से कई देश पीछे हट रहे हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। कुल मिलाकर, यह डील ट्रंप की रणनीति को चुनौती देती है और वैश्विक व्यापार को ज्यादा संतुलित बना सकती है।

व्यापक प्रभाव और संतुलित नजरिया

यह समझौता वैश्विक व्यापार में बड़े बदलाव का संकेत है, जहां अमेरिका का दबदबा कम हो रहा है। भारत और ईयू की डील से 20 अरब लोगों और 25 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी को कवर मिलेगा। अमेरिका को डर है कि ईयू उसका सबसे बड़ा साथी (30 प्रतिशत माल और 43 प्रतिशत सेवाओं का व्यापार) खो सकता है। चीनी विशेषज्ञ झोउ मी कहते हैं कि अमेरिका उम्मीद करता है कि सब उसके हिसाब से चलें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ओआरएफ के हर्ष पंत मानते हैं कि यह डील स्वतंत्र नीतियों का संकेत है। क्या यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को ज्यादा निष्पक्ष बनाएगा? यह सोचने की बात है, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ नीतियां बैकफायर कर रही हैं। भारत ने रूस से रिश्ते रखते हुए ईयू के साथ डील की, बिना अल्टीमेटम दिए। ईयू ने भारत की संवेदनशीलताओं का सम्मान किया, जैसे कृषि बाहर रखना। हालांकि, अमेरिका का दृष्टिकोण है कि यह यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है, लेकिन ईयू व्यापार को अलग रखता है।

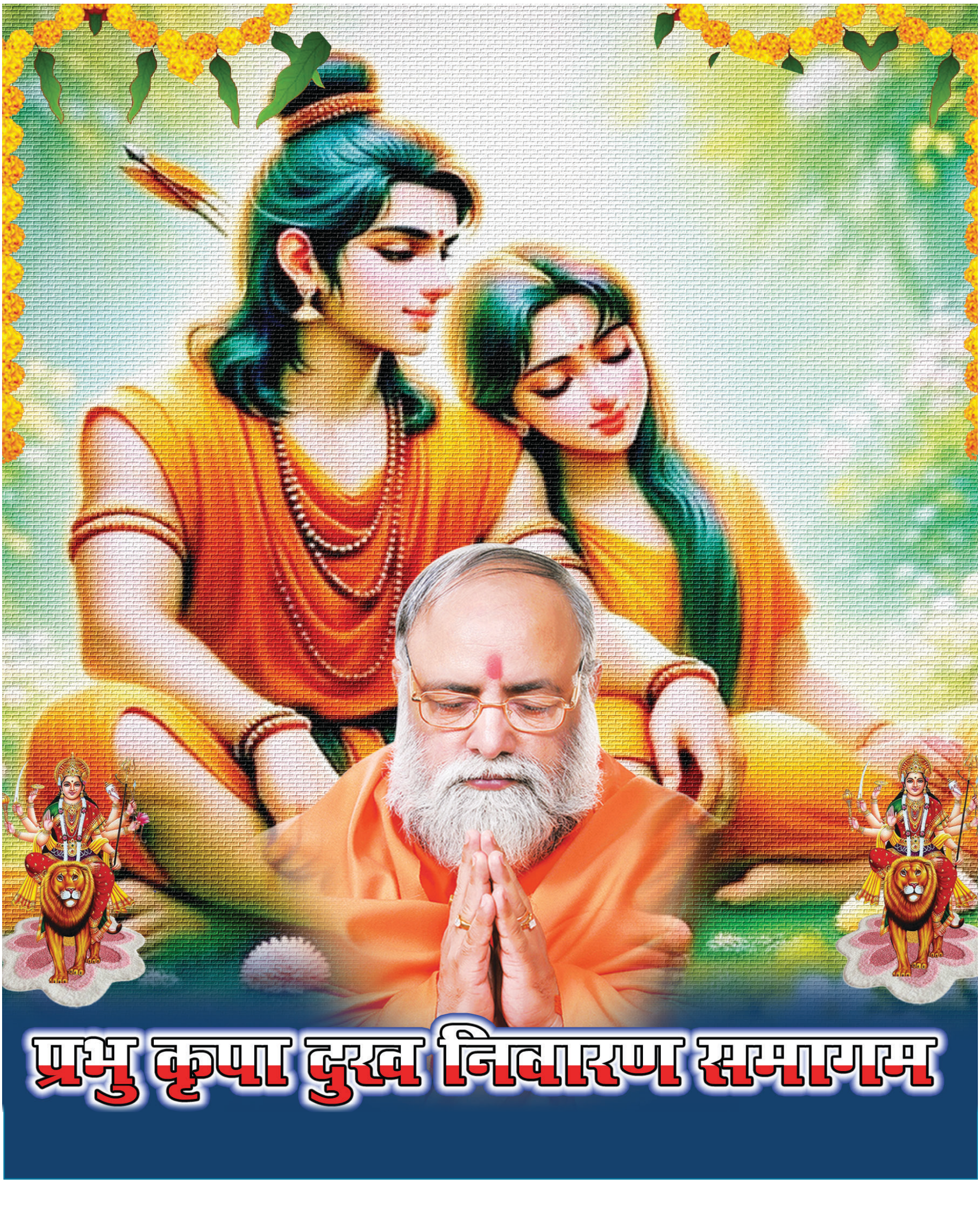
प्रभु कृपा दुख निवारण समागम

BY

Arihanta Industries

ULTIMATE HAIR SOLUTION

- BHRINGRAJ
- AMLA
- REETHA
- SHIKAKAI

100 ML

15 ML

NO ARITIFICIAL COLOR FRAGRANCE CHEMICAL

KESH VARDAK SHAMPOO

The complete solution of all hair problems:

- Prevent hair fall and make hair follicle strong.
- Promote hair growth.
- Free from all artificial & harmful chemicals like., SLS.
- 100% pure ayurvedic shampoo.
- Suitable for all hair types.

ORDER ONLINE @ :

amazon

arihanta.in

Arihanta Industries